शनिवार
22 अगस्त -2026
वर्ष 10, अंक 348
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची

रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

आसमान में नजर आएगा ब्लड मून, अद्भुत होगा नजारा !

अगस्त के आखिर में कई देशों में दिखेगा दुर्लभ चंद्र ग्रहण

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अगस्त का महीना खगोल वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए बेहद खास है। महीने की शुरुआत में जहां एक पूर्ण सूर्य ग्रहण आखिर में एक शानदार चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जिसे दुनिया के बड़े हिस्से में देखा जा सकेगा। इस दौरान पूर्णिमा का चांद पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा, जिससे आसमान में वह डरावने लाल रंग में नजर आएगा। इस दौरान चंद्रमा का 96 प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी की छाया में होगा और केवल एक पतला हिस्सा सीधे सूरज की रोशनी में होगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चांद, पृथ्वी और सूरज एक सीध में सामने आते हैं। इस दौरान चांद पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। हालांकि, चंद्र ग्रहण के दौरान चांद आसमान से गायब नहीं होता बल्कि यह गहरे लांल रंग में नजर आता है। इसी वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है। 27-28 अगस्त को होने वाला चंद्र ग्रहण को उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में अरबों लोग देखेंगे।

चांद का 96 फीसदी हिस्सा पृथ्वी की छाया में होगा

इसे पूरे उत्तरी अमेरिका में देखा जा सकेगा, लेकिन अमेरिका के पूर्वी हिस्से में ग्रहण का सबसे शानदार नजारा दिखेगा। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रहण जब अपने चरम पर होगा, उस दौरान इसका 96 फीसदी हिस्सा पृथ्वी की छाया में ढका होगा। अमेरिकी समयानुसार ग्रहण गुरुवार रात 9.38 बजे शुरू होगा और शुक्रवार सुबह लगभग 3.01 बजे खत्म होगा।

भारत में नहीं दिखाई देगा दुर्लभ चंद्र ग्रहण

27-28 को होने वाला गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों के साथ यूरोप और अफ्रीका के कुछ इलाकों में भी दिखाई देगा। कुछ जगहों पर काफी गहरा दिखेगा जबकि दूसरी जगहों पर इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिखाई देगा। हालांकि, इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में दिन हो रहा होगा। चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण के उलट, इसे बिना किसी खास चश्मे के नंगी आंखों से देखा जा सकेगा।

संक्षिप्त समाचार

अखिलेश-मायावती को योगी सरकार ने दी बुलेट प्रूफ जैकेट

- पहली बार 52 नेताओं को बांटी, इनमें राजभर, नंदी, अपर्णा यादव का भी नाम

लखनऊ (एजेंसी)। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव, मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री भी हैं। मंत्री

संजय निषाद, नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', ओपी राजभर, अपर्णा यादव को जैकेट मिल गई है। बुलेट प्रूफ जैकेट यूपी सरकार के सुरक्षा मुख्यालय ने खरीदी है। एक बुलेट प्रूफ की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मंत्री संजय निषाद ने बुलेटप्रूफ जैकेट मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा- उन्हें बुलेटप्रूफ जैकेट पहनना ही नहीं आता है। अब तक इसे पहनना नहीं सिखाया गया है। विधानसभा 2027 को देखते हुए सरकार ने एहतियातन यह फैसला लिया है।

कांग्रेस को घेर रही बीजेपी के गढ़ में ही हुआ 'खेला'

- नागपुर नगर निगम में वंदे मातरम के दो अंतरे गाने पर विवाद

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नागपुर में भाजपा शासित नागपुर नगर निगमकी आम सभा की बैठक के दौरान एक प्रशासनिक चूक सामने आई है। बैठक की शुरुआत में पारंपरिक रूप से गाए जाने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के दौरान केवल दो ही अंतरे गाए गए, जबकि केंद्र सरकार के हालिया निर्देशों के अनुसार इसके सभी अंतरों का पूर्ण गायन किया जाना अनिवार्य है। बता दें कि वंदे मातरम् के गायन को लेकर यह खबर ऐसे समय में सामने आई है।

तीन साल नहीं अब एक साल की वकालत करके भी बन सकेंगे जज

- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जज बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। निचली अदालतों में जज बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मई 2025 के फैसले में संशोधन करते हुए एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 साल की अनिवार्य वकालत की शर्त को घटाकर 1 साल कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, यहीं बैठा रहूंगा

- पैलेट गन मामले में धरने पर राहुल, अज्ञात के खिलाफ हुई एफआईआर

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर करीब 12.30 बजे से दिल्ली के संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोहबच की एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक वे यहां से हटेंगे नहीं। इस दौरान उन्होंने साहिल को पैलेट गन से लगे छर्रे दिखाए। उन्होंने कहा,पैलेट गन चलने के सबूत हैं। ये छर्रे साहिल के शरीर से निकले हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है। पुलिस कह रही है कि उन्हें एफआईआर नहीं करने के ऊपर से निर्देश हैं। हालांकि बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र साहिल घायल हो गए थे।

राहुल बोले-शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली

राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी जिद पर अड़े रहे।

देश भर में बढ़ गए स्वाइन फ्लू के मामले

एमपी में महिला की मौत,स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वाइन फ्लू से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला को कोई दूसरी बीमारी नहीं थी। मृतक की पहचान सरोज नागर (60) के रूप में हुई है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राजधानी की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फ्लू की मौजूदा स्थिति, अस्पतालों की तैयारियों, जांच और इलाज की सुविधाओं के साथ बीमारी को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की गई। यह बैठक दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी की खबरों के बीच हुई। इस साल दिल्ली में अब तक फ्लू के 1,349 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल सिर्फ 229 केस दर्ज किए गए थे।

मिजोरम में 5 आरोपी गिरफ्तार

मिजोरम के मामित जिला में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग असम से अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से संक्रमित 45 सुअर लेकर आए थे। सुअरों को आइजॉल ले जाया जा रहा था। आरोपी मिजोरम-असम बॉर्डर पर चेकिंग से निकल गए, बाद में इन्हें जामुआंग गांव में पकड़ा गया। स्वाइन फ्लू को आमतौर पर फ्लू कहा जाता है। यह इंफ्लूएंजा वायरस का एक प्रकार है। यह मुख्य रूप से सांस की नली को प्रभावित करता है। 2009 में स्वाइन फ्लू दुनियाभर में काफी फैला था। इसके बाद इंसानों में फैलने वाले मौसमी फ्लू के वायरस का हिस्सा बन गया। फ्लू ज्यादातर लोगों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में इसके गंभीर होने का खतरा ज्यादा रहता है। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं होती। हल्के मामलों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार आराम, पर्याप्त पानी और लक्षणों के हिसाब से इलाज किया जाता है।

जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हल्ला बोल

- ग्रामीणों ने बोला हमला, पीट-पीट कर गांव से भगाया

जयपुर (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर जयपुर में हमला हुआ है। रांका शुक्रवार सुबह 10 बजे बगरू के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर

वहां से खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। रांका के साथ मौजूद महिला समर्थकों पर गांव की महिलाओं ने मिट्टी फेंकी। रांका ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा- हमले में गाड़ियों के शीशे और मोबाइल तोड़े गए, एक महिला से मारपीट हुई और उनकी शर्ट फाड़ दी गई। टीम के एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। रांका ने कहा, आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी हो और स्कूल निरीक्षण रोकने का आदेश वापस लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे और दिलावर के इस्तीफे की मांग करेंगे।

भोजशाला के पास जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा थी पुख्ता

विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ,शंख बजाकर जयघोष

धार (एजेंसी)। धार में भोजशाला से सटे खसरा नंबर 612 पर जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को भारी तनाव रहा। हिंदू संगठन के सदस्य नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। शंख बजाकर जयघोष भी किया गया। वहीं, करीब 500 नमाजी निर्धारित स्थान पर नमाज अदा करने पहुंचे। खसरा नंबर 612 के मेन गेट तक नमाजियों की भीड़ रही। प्रशासन और पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। भोजशाला के प्रवेश द्वार, बाहरी क्षेत्र और नमाज स्थल पर

बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। करीब 1,000 जवानों का बल सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी निगरानी की जा रही थी।

भोज उत्सव समिति बोली- हर शुक्रवार करते आए हैं हनुमान चालीसा

भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे ने कहा- हम तो प्रत्येक शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते आए हैं और करते रहेंगे। हमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का जो अधिकार हिंदू समाज को मिला है, उसी के तहत हम पूजा-पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा- उससे (नमाज से) हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमें तो सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का अधिकार मिला है।

अमरीका नहीं जा पाएंगे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी

केंद्र का झटका,अमेरिका जाने की नहीं मिली परमीशन

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सीएमओ के मुताबिक, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाला तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरा नहीं कर सकेगा। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से इनकार किया है। रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं। उन्हें अमेरिका के बोस्टन जाना था और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटना था, लेकिन अब वे 23 अगस्त को सीधे हैदराबाद लौटेंगे। हालांकि, सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका जाए बिना वहां के संस्थानों के साथ सभी एमओयू और साझेदारी समझौते पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

पहले से तय था यूके और यूएस का दौरा

रेवंत रेड्डी 20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे। यूके दौरे में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन बिजनेस स्कूल के कार्यक्रम शामिल थे। उन्हें एमिरेट्स स्टेडियम में फुटबॉल से जुड़े कार्यक्रम में भी जाना था। इसके बाद 24 अगस्त को अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का कार्यक्रम था।

22 एवं 23 अगस्त को आयोजित दूसरे एवं अंतिम विशेष शिविर में प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ने में सहयोग करें—के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आगामी शनिवार एवं रविवार, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाले दूसरे एवं अंतिम विशेष शिविर को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने में सहयोग करें कि राज्य का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को अथवा उससे पहले 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है अथवा हो जाएगी और जिनका नाम एसआईआर के अंतर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणापत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन अवश्य जमा करें। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे पात्र नागरिकों को चिन्हित कर आवेदन जमा कराने में सहयोग करने की अपील की।पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया है कि वे नगर निगम एवं शहरी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को एसआईआर में भाग लेने एवं एसआईआर वाले मतदाता सूची में अपना नाम सूचीबद्ध कराने हेतु अपने स्तर से प्रचार प्रसार अवश्य करें। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जानकारी दी कि शहरी क्षेत्र में वार्ड सदस्य एवं पूर्व वार्ड सदस्यों की बैठक संबंधित एईआरओ स्तर पर आयोजित करेंगे। वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को सहयोग करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान 'एक परिवार-एक मतदान केंद्र' की व्यवस्था को भी प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाना है। यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं अथवा उनका वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से दूर है, तो परिवार के सदस्यों को उनके निवास के निकट एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि ऐसे मतदाता जो वर्तमान में झारखण्ड राज्य के सामान्य निवासी हैं, लेकिन उनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी अपने वर्तमान झारखण्ड के पते से संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 एवं निर्धारित घोषणापत्र भरकर आवेदन अवश्य जमा करें।पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि 22 एवं 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित विशेष शिविर में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। पात्र नागरिक संबंधित प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए श्वष्टद्धह्यश्ञ्.श्वश्च अथवा भारत निर्वाचन आयोग के ङ्क्षश्वह्लद्गह्म्' स्द्गह्म्1द्बष्द्ग क्कश्वह्म्ह्लड्डद्य का भी उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है। इसमें राजनीतिक दलों, बीएलए-2, बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर तथा नागरिकों की सक्रिय सहभागिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो इस हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। कोई विदेशी नागरिक अगर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए गलत घोषणापत्र भरकर गलत तरीके से शामिल होने की कोशिश कर रहें है तो उनका फॉर्म 7 भरकर अपील करें, ईआरओ स्तर पर इनकी सुनवाई करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

एचईसी के पुनरुद्धार: केंद्रीय संसदीय उप-समिति ने सीएम से की मुलाकात

रांची, एजेंसी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) लिमिटेड के पुनरुद्धार को लेकर गठित छह सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप-समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एचईसी की मौजूदा स्थिति और इसके पुनरुद्धार की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में एचईसी की वर्तमान वित्तीय एवं औद्योगिक स्थिति के साथ संस्थान को फिर से मजबूत करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श हुआ। समिति के सदस्यों ने एचईसी के पुनरुद्धार के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य के स्तर पर समन्वय के माध्यम से एचईसी को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयासों को गति देने पर जोर दिया गया। एचईसी देश के महत्वपूर्ण भारी इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल रहा है। रांची स्थित इस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान ने देश के विभिन्न बड़े औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया है। ऐसे में इसके पुनरुद्धार को लेकर केंद्र की संसदीय उप-समिति की सक्रियता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पलामू टाइगर रिजर्व युवाओं को देगी एआई की ट्रेनिंग, 22 अगस्त से शुरू होगा अभियान

पलामू, एजेंसी। पलामू टाइगर रिजर्व पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाकों में रहने वाले युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देगा। आज के वैज्ञानिक युग में पलामू टाइगर रिजर्व के युवाओं को यह ट्रेनिंग मुफ्त में दिया जाना है। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के एनआईसी के समागार में 22 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। पलामू टाइगर रिजर्व, एआई एक्सपर्ट और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना ने बताया कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ गया है। ग्रामीण इलाके की युवाओं एवं सभी लोगों को इससे संबंधित ट्रेनिंग देने की योजना तैयार की गई है। पीटीआर उपनिदेशक ने कहा कि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी भी है। इन्हें भी इस अभियान से जोड़ा जाना है और उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अभियान का 'आई बिल्डर बूट कैंप' नाम दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व ने हुनर से रोजगार अभियान के तहत 600 से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में ट्रेनिंग दिया गया है। अब इस अभियान के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दिया जाना है। पीटीआर के इलाके की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।

चतरा में जिस्मफरोशी के खिलाफ कार्रवाई, चांदनी रेस्टोरेंट में छापेमारी

चतरा, एजेंसी। शहर के न्यू परिसदन भवन के समीप स्थित चांदनी रेस्टोरेंट में जिस्मफरोशी की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें, पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी के निर्देश पर एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इस दौरान मौके से पुलिस ने पांच युवती, चार युवक और रेस्टोरेंट संचालक के बेटे को हिरासत में लिया। सभी को पूछताछ के लिए सदर थाना ले जाया गया है। पुलिस के अनुसार, रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन करने के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अचानक रेस्टोरेंट में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद युवक-युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रेस्टोरेंट संचालक के बेटे को भी पुलिस अपने साथ थाना ले गई। छापेमारी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गयी है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थीं और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं। पुलिस कार्रवाई के बाद शहर में मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एसडीपीओ सन्नी वर्धन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पांच युवतियों, चार युवकों और रेस्टोरेंट संचालक के बेटे को पकड़कर सदर थाना लाया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ ने कहा कि जिस्मफरोशी जैसे धंधे में संलिप्त होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

रेलवे लाइन के लिए ग्रामसभा का विरोध, सेरेनदाग में ग्रामीणों ने दुकानें बंद कर मनाया काला दिवस

टंडवा, एजेंसी। आम्रपाली-चंद्रगुप्त परियोजना के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन निर्माण को लेकर सेरेनदाग गांव में प्रस्तावित ग्रामसभा का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। अब तक कई बार ग्रामसभा आयोजित की गयी, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध करते हुए इसका बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए अंचल प्रशासन ने एक बार फिर प्रस्तावित ग्रामसभा को स्थगित कर दिया। इसके बावजूद शुक्रवार को सेरेनदाग के ग्रामीणों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया।अंचल अधिकारी, टंडवा की ओर से जारी पत्र में सेरेनदाग में रेलवे लाइन निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के भू-हस्तांतरण के संबंध में वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत ग्रामसभा आयोजित करने की बात कही गयी थी। पत्र के अनुसार ग्रामसभा 21 अगस्त को बाजार टांड़ में प्रस्तावित थी। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सहमति और मांगों का समाधान किये बिना जमीन से संबंधित प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ायी जानी चाहिए।

परीक्षा रद्द होने से अधिकारियों और कर्मचारियों के पद खाली,

जिला से सचिवालय तक कामकाज हुआ बाधित!

रांची, एजेंसी। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद का असर अब केवल अभ्यर्थियों के भविष्य तक सीमित नहीं रह गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के पद खाली हो गए हैं। इसका सीधा असर जिलों से लेकर प्रखंड, अंचल और सचिवालय तक के सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है।

वहीं दूसरी तरफ नए डीएसपी बने से लेकर कई के सपने टूट कर बिखर गए। सरकार में एक तरफ अधिकारियों की कमी से कई जगह दोहरी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया है, तो दूसरी ओर जिन युवाओं ने चयन के बाद नौकरी ज्वाइन कर ली थी, उनके सामने अचानक भविष्य का संकट खड़ा हो गया है।

झारखंड सरकार ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले चुकी है। जेएसएससी सीजीएल और टीडीपीएल के माध्यम से हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। इस फैसले का सबसे सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जिन्हें सीजीएल परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से अलग-अलग सरकारी विभागों में करीब 1975 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इनमें कई तरह के पद शामिल हैं। यानी सरकार का फैसला केवल एक विभाग या एक पद पर लागू नहीं हुआ, बल्कि सीजीएल के जरिए चयनित अलग-अलग पदों पर असर पड़ा है। इन पदों में मुख्य रूप से, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो जैसे पद शामिल हैं। इन पदों पर ष्टतरु परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और कई लोग नौकरी भी कर रहे थे।

सरकार से मिले आकड़ों के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा में कुल 1450 पद स्वीकृत हैं। इनमें 342 पद परीक्षा रद्द होने के कारण खाली हो गए हैं। 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जरिए डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित 207 अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 में नौकरी ज्वाइन की थी। नियुक्ति के बाद इन अधिकारियों को प्रशासनिक कामकाज की ट्रेनिंग के लिए एटीआई भेजा गया था।

मार्च 2026 में उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग जिलों में भेजा गया। कई जिलों में उपायुक्तों ने प्रशासनिक जरूरत के

अनुसार इन अधिकारियों को प्रखंड और अंचल स्तर की जिम्मेदारियां भी दे दी थीं। यानी जिन अधिकारियों ने सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनकर काम शुरू कर दिया था, उनके सामने अब परीक्षा रद्द होने के बाद नौकरी का संकट खड़ा हो गया है।

सबसे ज्यादा भावनात्मक असर उन चयनित डीएसपी पर पड़ा है, जो लंबे समय तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बाद चयनित हुए। चयन के बाद 35 की ट्रेनिंग शुरू हुई और अब वे फील्ड में पदस्थापन की तैयारी में थे। उन्हें लग रहा था कि वर्षों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और अब वे पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे लेकिन परीक्षा रद्द होने के फैसले ने एक झटके में उनकी पूरी तस्वीर बदल दी। जिन युवाओं ने ट्रेनिंग पूरी की, सरकारी सेवा में योगदान दिया और पदस्थापन का इंतजार किया, उन्हें अब अपनी नौकरी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों के लिए यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है। चयन के बाद परिवार ने भविष्य की योजनाएं बनाईं, आर्थिक स्थिति को स्थिर मान लिया और युवाओं ने अपने करियर की दिशा तय कर ली थी। अब अचानक नौकरी पर ही संकट खड़ा होने से उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल 335 पदों पर चयनित अभ्यर्थी इस फैसले से प्रभावित हुए हैं, इनमें सबसे अधिक 205 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं। पदवार देखें तो डीएसपी के 35, डिप्टी कलेक्टर के 205, फाइनेंस सेवा के 54, एजुकेशन सर्विस के 9, जेल सर्विस के 2, होम कमांडेंट के 1, प्रोबेशन सर्विस के 5, लेबर सर्विस के 13, कोऑपरेटिव सर्विस के 8 और एक्साइज के 3 पद शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जिस परीक्षा के आधार पर इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उसके रद्द होने के बाद उनकी नियुक्ति का क्या होगा। यदि परीक्षा का परिणाम और उससे जुड़ी चयन प्रक्रिया ही निरस्त मानी जाती है, तो नियुक्ति की वैधता भी सवालों के घेरे में आ सकती है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता उन अभ्यर्थियों की है, जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा पास की और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकारी नौकरी की उम्मीद में थे। परीक्षा रद्द होने के बाद अब उनके सामने नौकरी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।

परीक्षा रद्द होने से मैनपावर में भी भारी कमी हो गई है। संकट केवल जिलों और प्रखंडों तक सीमित नहीं है। सचिवालय में भी कर्मचारियों की कमी हो गई है। जेएसएससी-सीजीएल के जरिए 1932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इनमें से 1927 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इन नियुक्तियों से सरकार के विभिन्न विभागों को बड़ी संख्या में कर्मचारी मिले थे। इनमें 847 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 288 कनीय सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, 178 अंचल निरीक्षक और चार प्लानिंग असिस्टेंट शामिल थे। सिर्फ 847 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और 288 कनीय सचिवालय सहायकों को मिलाकर 1135 कर्मचारी सचिवालय की व्यवस्था में जुड़े थे। इनके हटाने का असर फाइलों के निपटारे और विभागीय कामकाज पर पड़ रहा है।

सीखने की क्षमता का निरंतर विकास करें-नितिन मदन कुलकर्णी

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

सरला बिरला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नए विद्यार्थियों के लिए 'एआई युग के लिए अपनी सोच और सीखने की क्षमता के विकास' विषय पर शुक्रवार को एक्सपर्ट टॉक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नितिन मदन कुलकर्णी, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल, झारखंड ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलकर्णी ने तकनीक को अपनाने, सीखने की क्षमता को निरंतर विकसित करने तथा निर्धारित पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर नवीन कौशल अर्जित करने पर जोर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि केवल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र दीर्घकालिक करियर सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। अतएव लक्ष्य पर बाज जैसी नज़र रखें।एआई पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे नौकरियों की प्रकृति बदल रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को इसका प्रयोग सीखने के क्रम में सहायक के रूप में करने तथा अपने कार्य और सोच को पूरी तरह एआई पर निर्भर न करने की सलाह दी। उन्होंने आलोचनात्मक चिंतन, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, तथ्यों का सत्यापन, एकाग्रता, ध्यान और निरंतरता के महत्व पर विशेष जोर दिया। महत्व के दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए उन्होंने एथिकल जजमेंट, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस के महत्व पर जोर दिया।सत्र में कुलकर्णी ने अपने अनुभवों एवं विचारों को साझा करते हुए विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया।एक्सपर्ट टॉक के अवसर पर सरला बिरला विवि के महानिदेशक प्रो. गोपाल पाठक, कुलपति प्रो. सी. जगनाथन, कुलसचिव प्रो. एस. बी. दंडीन, विवि के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।एसबीयू में एक्सपर्ट टॉक के आयोजन पर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति बिजय कुमार दलान एवं राज्यसभा सांसद सह निदेशक, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने हर्ष व्यक्त किया है।

सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो नवजात को दिया आशीर्वाद

दैनिक अलग पहचान, शीतल दत्ता, ब्यूरो चीफ, धनबाद /

धनबाद सिंदरी। चांदकुइया के वरिष्ठ भाकपा माले नेता मानिक बाउरी के पोते एवं 'सी न्यूज भारत' (C News Bharat) के न्यूज रिपोर्टर सिंधु बाउरी के भतीजे के छठियारी (छठी उत्सव) के शुभ अवसर पर सिंदरी विधानसभा के विधायक चंद्रदेव महतो ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्सव में पहुंचे विधायक ने नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर भरपूर दुलार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चे के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु स्वास्थ्य की मंगल कामना की। इस सुखद पारिवारिक आयोजन के दौरान विधायक जी ने परिवार के सभी सदस्यों से आत्मीय मुलाकात कर अपनापन और प्रेम प्रकट किया। इस विशेष एवं हर्षोल्लास के अवसर पर मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि सह मीडिया प्रभारी शीतल दत्ता, रमेश महतो, पुरुषोत्तम दे, रोहित महतो, विजय राम, चंदन भूमिहार, निलेश महतो और हारु बाउरी उपस्थित रहे। इनके अलावा बाउरी परिवार के सदस्य, सगे-संबंधी एवं भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण इस मांगलिक उत्सव का हिस्सा बने।

चार वर्षीय यूजी में 75 प्रतिशत अंक पर पीएचडी का रास्ता आसान, पीजी की अनिवार्यता खत्म

रांची, एजेंसी। आरयू में पीएचडी प्रवेश को लेकर पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय ने यूजीसी-2022 के प्रावधानों और नई शिक्षा नीति के अनुरूप पीएचडी के नए नियम तैयार किए हैं। नई व्यवस्था में चार वर्षीय स्नातक डिग्री करने वाले विद्यार्थियों के लिए शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता आसान किया गया। अब चार वर्षीय यूजी में 75 प्रतिशत अंक या निर्धारित समकक्ष सीजीपीए हासिल करने वाले विद्यार्थी पीएचडी में सीधे प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को पीएचडी में जाने से पहले अलग से पीजी डिग्री करना जरूरी नहीं होगा।

रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजकुमार शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था यूजीसी-2022 और नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले योग्य विद्यार्थियों को पीएचडी में प्रवेश का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही शोध प्रवेश प्रक्रिया, कोर्स वर्क और पीएचडी की अवधि को लेकर भी नए प्रावधान तय किए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत मास्टर डिग्री या एमफिल वाले अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंक की पात्रता बनी रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता अंक में पांच प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। चार वर्षीय यूजी में निर्धारित 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सीधे पीएचडी के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा।

इससे स्नातक स्तर पर ही शोध के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा। पीएचडी प्रवेश में राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाओं को भी महत्व दिया गया है। नेट, सीएसआईआर नेट, गेट और जीजीईटी जैसी परीक्षाओं में पात्र अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा से छूट का प्रावधान है। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शोध पद्धति और संबंधित विषय से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया जाएगा।

विद्यार्थियों को करियर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस की मिली जानकारी

दैनिक अलग पहचान डेस्क संवाददाता,रांची/

रांची: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की करियर काउंसलिंग कमेटी की ओर से देशभर में आयोजित करियर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस फॉर यूथ एवं सुपर मेगा काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत रांची में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जवाहर विद्या मंदिर श्यामली, विवेकानंद विद्या मंदिर धुर्वा तथा फिरायालाल पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों में करीब 2000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को लेखांकन एवं वित्त के क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय और चार्टर्ड अकाउंटेंसी को करियर के रूप में अपनाने की संभावनाओं की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान आर्थिक परिवेश में अकाउंटिंग और फाइनेंस की भूमिका लगातार बढ़ रही है। सीए अब केवल ऑडिट और टैक्सेशन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, निवेश, कंपनी प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, कंसल्टेंसी, अंतरराष्ट्रीय वित्त और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एफजेसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सीए रंजीत गरोड़िया, पूर्व क्षेत्रीय परिषद सदस्य सीए मनीषा बियानी, रांची शाखा की पूर्व अध्यक्ष सीए श्रद्धा बगला एवं सीए हरदीप कौर भसीन ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सीए पाठ्यक्रम की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, अध्ययन के विभिन्न चरणों, प्रशिक्षण और परीक्षा प्रणाली की जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें नियमित अध्ययन, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) राजीव मनोहर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में लेखांकन एवं वित्त के क्षेत्र में कुशल विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप करियर का चयन करते हुए निरंतर मेहनत से लक्ष्य हासिल करना चाहिए। उन्होंने करियर जागरूकता के लिए आईसीएआई के प्रयासों की सराहना की। आईसीएआई रांची शाखा के अध्यक्ष सीए अनिश जैन ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जो विद्यार्थियों को अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और फाइनेंस के अलावा कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर देता है। शाखा के उपाध्यक्ष सीए विवेक खोवाल ने कहा कि सीए युवाओं को ज्ञान, सम्मान और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। वहीं सचिव सीए दिलीप कुमार ने कहा कि सीए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में व्यावसायिक ज्ञान के साथ निर्णय लेने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी मदद करता है। कार्यक्रम में आईसीएआई रांची शाखा के निवर्तमान अध्यक्ष सीए अभिषेक केडिया, अमिताभ लाहा, प्राचार्य विवेकानंद विद्या मंदिर; हनीत कौर मुंजाल, प्राचार्य फिरायालाल पब्लिक स्कूल; बी.एन. झा, प्राचार्य जवाहर विद्या मंदिर श्यामली तथा डॉ. जी.सी. बास्के, समन्वयक, वाणिज्य विभाग, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।रांची में कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के आकाश कुमार, फिरायालाल पब्लिक स्कूल की डॉ. मोनिका भाटिया तथा जेवीएम श्यामली के डॉ. मोती प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

बोकारो में महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दे रहा डालमिया भारत फाउंडेशन

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

बोकारो: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में डालमिया भारत फाउंडेशन (डीबीएफ) ने बोकारो की गोरावाली साउथ पंचायत के बिश्नुपुर गांव में टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है। डालमिया भारत लिमिटेड की सीएसआर शाखा डीबीएफ की इस पहल के तहत फिलहाल दो बैचों में कुल 50 महिलाएं सिलाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण ले रही हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सिलाई का हुनर प्रदान कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं सिलाई का काम, घर से काम या अपना छोटा टेलरिंग व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इससे उन्हें हर महीने करीब 6,000 रुपये तक की आय अर्जित करने का अवसर मिल सकता है। इसके जरिए महिलाएं परिवार की आय में योगदान देने के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। यह सेंटर डीबीएफ के महिला स्किलिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे देशभर में विभिन्न केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं तक वोकेशनल ट्रेनिंग की पहुंच बढ़ाना और उन्हें बेहतर कमाई के अवसर उपलब्ध कराना है। इस पहल पर डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड के यूनिट हेड-बोकारो, सुनील कुमार भुसारी ने कहा कि टेलरिंग ऐसा काम है, जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है और स्थानीय स्तर पर भी आसानी से किया जा सकता है। जब महिलाओं के पास अपने हुनर का इस्तेमाल करने और घर व समुदाय की आमदनी में योगदान देने के मौके होते हैं, तो इसका फायदा सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रहता। इससे देश की तरक्की में भी मदद मिलती है। हमारी स्किलिंग पहलों के जरिए हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने समुदाय की तरक्की में भाग लेने और योगदान देने के लिए जरूरी हुनर और अवसर मिल सकें। टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन बोकारो के एलडीएम प्रकाश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन, बैंकिंग और विकास से जुड़े संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें सुदीप सिन्हा, जीएम, डीआईसी, बोकारो; सुरिना, डीडीएम, नाबार्ड, बोकारो; और नेहा पराशर, डायरेक्टर, जेएसएस, बोकारो शामिल रहीं।

कार्यक्रम में संजय झा, एचआर प्रमुख, डीसीबीएल बोकारो; विनोद कुमार सिंह, टेक्निकल हेड, डीसीबीएल बोकारो सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं, गणेश ठाकुर, मुखिया एवं पीआरआई प्रतिनिधि, विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए। डालमिया भारत फाउंडेशन की यह पहल समावेशी विकास, स्थायी आजीविका और ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाती है। कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय समुदायों को ऐसे व्यावहारिक और टिकाऊ अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है, जिनसे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखण्ड राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026 के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 भरने के लिए दो दिवसीय द्वितीय एवं अंतिम विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है।इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि यह शिविर शनिवार 22 अगस्त और रविवार 23 अगस्त 2026 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होगा।शिविर में वैसे भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या अहर्ता तिथि 01.10.2026 तक 18 वर्ष पूर्ण होने वाली है वे मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भर सकते हैं। वहीं परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक साथ नजदीकी मतदान केंद्र में स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भर सकते हैं।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

संक्षिप्त समाचार

विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, बीडीएस ने खंगाला पूरा परिसर

रांची, एजेंसी। एक अज्ञात शख्स ने 12 अगस्त को विधानसभा के कुछ कर्मचारियों को फोन कर विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। फोन करने वाले ने कर्मचारियों से विधानसभा नहीं जाने की बात भी कही। मामले को लेकर रांची के विधानसभा थाने में आज स्न्ढ्ढक्रदर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस धमकी की जानकारी पुलिस को 20 अगस्त को मिली। मामला सामने आते ही रांची पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल विधानसभा परिसर की सुरक्षा जांच कराई। बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) की टीम ने पूरे विधानसभा परिसर को बारीकी से खंगाला। हर संभावित स्थान की जांच की गई, लेकिन टीम को कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। जांच के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों के मुताबिक धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। आरोपी की पहचान के लिए तकनीकी टीम को लगाया गया है। पुलिस कॉल की पूरी डिटेल खंगालने के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर धमकी किसने और किस मकसद से दी। यह पहली बार नहीं है जब रांची में सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो। इससे पहले सिविल कोर्ट, डीसी कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों को भी धमकियां मिल चुकी है। सिविल कोर्ट और डीसी कार्यालय को तो कई बार निशाना बनाने की धमकी दी गई। हर बार बीडीएस टीम ने जांच की, लेकिन धमकियां अफवाह साबित हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा ऐसे ही एक मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद थी कि इस तरह की धमकियों पर रोक लगेगी। इसके बावजूद झारखंड के अलग-अलग शहरों में धमकी के मामले सामने आते रहे हैं। इनमें अधिकांश धमकियां ईमेल के जरिए भेजी गई है। विधानसभा का मामला इसलिए अहम है, क्योंकि यहां पहली बार कॉल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई है।

अयोध्या-वाराणसी घूमना हुआ आसान, कोल इंडिया कर्मचारियों को 400 रुपए में मिलेगा कमरा

रांची, एजेंसी। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए अयोध्या और वाराणसी में हॉलिडे होम की सुविधा शुरू की है। दोनों शहरों में कर्मचारियों के लिए दो-दो कमरे उपलब्ध होंगे। यह व्यवस्था एक सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2028 तक के अनुबंध के तहत संचालित होगी। कर्मचारियों को दोनों स्थानों पर कमरा लेने के लिए प्रतिदिन 400 रुपये का शुल्क देना होगा। कोल इंडिया के सर्कुलर के अनुसार, अयोध्या में कल्याण केके होटल्स, रामपथ, अयोध्या में दो कमरे उपलब्ध रहेंगे। वहीं वाराणसी में सफायर ग्रांड में दो कमरों की व्यवस्था की गयी है। इस सुविधा का लाभ केवल कोल इंडिया के कर्मचारी ही उठा सकेंगे। आवेदन के साथ कर्मचारी के परिवार के सदस्यों से संबंधित निर्धारित घोषणा-पत्र भी संलग्न करना होगा। आवेदन संबंधित कर्मचारी के नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से भेजना होगा। इसके अलावा 400 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से पूरी राशि का डिमांड ड्राफ्ट कोल इंडिया के पक्ष में जमा करना होगा। नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी किसी एक होटल में अधिकतम तीन दिनों के लिए कमरा बुक कर सकता है। किसी एक स्थान पर एक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो कमरे आवंटित किये जा सकते हैं। बुकिंग वास्तविक आरक्षण की तारीख से 75 दिन पहले शुरू होगी।

15 साल से नहीं बनी करमा-सदाफर सड़क, बारिश में ग` बने जानलेवा, ग्रामीण परेशान

मयूरहंड, एजेंसी। करमा-सदाफर सड़क इन दिनों गड्ढों और जलजमाव के कारण तालाब में तब्दील हो गयी है। बरसात के मौसम में इस सड़क से गुजरना दुर्घटना को आमंत्रण देने के समान है। सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर जाने के कारण वे दिखाई नहीं देते। इससे राहगीरों के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करमा-सदाफर सड़क की लंबाई करीब 11 किलोमीटर है। यह सड़क चौपारण हाइवे पथ को जोड़ती है और आसपास के ग्रामीणों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण मार्ग है। सांसद प्रतिनिधि सुधीर यादव ने कहा कि सड़क की स्थिति बेहद दयनीय है। सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर सवालों की बौछार

याचिकाकर्ता और रिफॉर्म्स मंच दोनों ही मांग रहे हैं

रांची, एजेंसी। झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ-साथ सीडीपीओ की नियुक्ति को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, इससे इन परीक्षाओं के जरिए चुने गए उम्मीदवारों को राहत मिली है, वहीं याचिकाकर्ताओं और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने इस मामले में राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं।

चाईबासा में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर पोस्टेड रहे दीपक कुमार सिंह भी इस मामले में याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि 25 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के दबाव में सरकार ने बिना किसी ठोस जांच के नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला ले लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जांच के इस तरह नियुक्तियां रद्द करना लोकतंत्र में कितना जायज है।

दीपक कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि हाईकोर्ट पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर देखेगा और न्यायसंगत फैसला देगा। उन्होंने कहा कि अदालत से राहत मिलने के बाद उन्हें खुशी है कि उन्हें न्याय मिला है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जिन अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सरकार के फैसले से प्रभावित हुई हैं, उन्हें भी जल्द अदालत से न्याय मिलेगा। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े सदस्य राजेश प्रसाद ने कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ और स्नस्ह्र में सफल होकर नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा, वहीं मंच की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि राज्य सरकार को जिस मजबूती के साथ अपना पक्ष अदालत के सामने रखना चाहिए था, वह नहीं रखा गया।

राजेश प्रसाद ने कहा कि सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण कमी सामने आई। जब अदालत ने सरकार से पूछा कि नियुक्तियों को किस आधार पर समाप्त किया गया, परीक्षाओं और नियुक्तियों को किस आधार पर रद्द किया गया और लोगों को नौकरी से हटाने का आधार क्या है, तब राज्य के महाधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इन सवालों का मजबूती

से जवाब नहीं दिया जा सका। उन्होंने कहा कि छात्रों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए अपना आंदोलन समाप्त किया था। मंत्रियों की बात मानी गई और सीआईडी जांच पर भी विश्वास किया गया। लेकिन हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस भरोसे के साथ छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया, सरकार उस भरोसे पर खरी नहीं उतर सकी। राजेश प्रसाद ने सरकार और मंत्रियों से एक बार फिर आग्रह करते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में छात्रों के साथ है, तो सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों के चयन से जुड़े जो भी साक्ष्य जांच में सामने आए हैं, उन्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी सहित टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं में कथित सेटिंग, पैसे के लेन-देन और अनियमित चयन से संबंधित जो तथ्य जांच में सामने आए हैं, उनका काउंटर सरकार को प्रमुखता से अदालत में रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों से जो भरोसे की बात की थी, अब उस भरोसे को जीतने और कायम रखने की जरूरत है। इधर, जेएसएससी-जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच के अनशन पर बैठने वाले राहुल क्रांति ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई मामला अदालत में जाता है तो कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनती है। राहुल क्रांति ने कहा कि अब सरकार को भी अदालत के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील और तथ्यों के आधार पर मामले का अंतिम निष्पादन होगा।

हीमोफिलिया सोसाइटी ने झारखंड में काउंसलिंग के लिए ष्टस्न्हेमंत सोरेन से की हस्तक्षेप की मांग, दिव्यांग आरक्षण से जुड़ा है मामला

रांची, एजेंसी। नीट 2026 की ओर से एमबीबीएस काउंसलिंग शुरू होने से पहले हीमोफीलिया सोसाइटी की रांची स्थित शाखा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उसने झारखंड में नीट-2026 के सफल प्रतियोगियों के लिए शुरू होने वाली काउंसलिंग से पहले ब्लड डिसऑर्डर की वजह से होने वाले दिव्यांग के लिए आरक्षण का लाभ देने की कोई व्यवस्था नहीं होना का जिक्र किया है। हीमोफीलिया सोसाइटी के रांची चैप्टर के सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने राज्य के उन छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए बताया कि रक्त संबंधी गंभीर बीमारियों- हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से ग्रसित दिव्यांगों के साथ नीट-26 के अधिकार का हनन हो रहा है। हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची चैप्टर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

हीमोफीलिया सोसाइटी, रांची चैप्टर के सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार का दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 19 अप्रैल 2017 से पूरे देश में प्रभावी है। इस अधिनियम में रक्त संबंधी विकारो हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और को 'विशिष्ट दिव्यांगता' की श्रेणी में रखा गया है। अधिनियम की धारा 3, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 25, 32 और 37 के मुताबिक, इन रोगों से ग्रसित सभी दिव्यांगजनों को दूसरे दिव्यांगजनों के समान अधिकार और हकदारी हासिल है, जिसमें 4% आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है लेकिन झारखंड में हृश्वश्वञ्ज 2026 का रिजल्ट घोषित होने के बाद जब राज्य स्तरीय काउंसलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आवेदन फॉर्म में रक्त संबंधी दिव्यांगता के लिए कोई विकल्प ही नहीं दिया गया है।

रांची में यूपीएससी मुख्य परीक्षा शुरू, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची, एजेंसी। देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 शुक्रवार से शुरू हो गई। रांची में भी परीक्षा के लिए डोरंडा स्थित निर्मला कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, रांची में करीब 200 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है और शुक्रवार को परीक्षार्थी निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। निर्मला कॉलेज परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह

निषेधाज्ञा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त को सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। रांची के एसडीएम कुमार रजत ने बताया कि परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी और सरकारी कार्यक्रम या शवयात्रा को इससे अलग रखा गया है। निषेधाज्ञा के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या हरवे-हथियार लेकर चलने तथा परीक्षा केंद्र के आसपास बैठक या आमसभा आयोजित करने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। एसडीएम कुमार रजत ने कहा कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से भी परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के बाद परीक्षार्थी निर्धारित नियमों के तहत परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

आरटीई के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी में 89 बच्चों का चयन, एक सप्ताह में होगा निजी विद्यालयों में नामांकन

रांची, एजेंसी। जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित इस लॉटरी में 35 निजी विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन किया गया है। चयनित बच्चों को संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के नामांकन मिलेगा और कक्षा आठवीं तक उनकी शिक्षा नि:शुल्क होगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई। समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में उप विकास आयुक्त संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की गई। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रीमा कुजूर, एडीपीओ समेत शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। ऋक्षश्व अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ब) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन्हीं आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कराई गई। इस चरण में कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सभी 224 आवेदन लॉटरी के लिए योग्य पाए गए। जिले के 39 मान्यता प्राप्त निजी में दूसरे चरण के लिए कुल 183 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 35 विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन हुआ। जिला प्रशासन के अनुसार, नामांकन के दोनों चरणों को मिलाकर अब तक कुल 722 सीटों पर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावकों को अब संबंधित विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूलों को चयनित बच्चों का नामांकन एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऋक्षश्व के तहत चयनित बच्चों से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि ऑनलाइन लॉटरी की पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से सुरक्षित रखते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई।

श्रावणी मेला से चमकी किसानों की किस्मत, फूलों की खेती ने लिया कुटीर उद्योग का रूप

देवघर, एजेंसी। श्रावणी मेला सिर्फ श्रद्धालुओं और शहर के छोटे-बड़े कारोबारियों के लिए ही कमाई का अवसर लेकर नहीं आया, बल्कि देवघर के ग्रामीण इलाकों के किसानों की आमदनी भी इससे बढ़ी है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में फूलों की बढ़ती मांग ने आसपास के गांवों में फूलों की खेती को कुटीर उद्योग का रूप देना शुरू कर दिया है। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से फूलों की खपत बढ़ी है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय किसानों को मिल रहा है।

दरअसल, बाबा मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को फूल अर्पित कर पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसे में फूलों की मांग लगातार बनी हुई है। इस मांग को पूरा करने में देवघर के आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसान अहम भूमिका निभा रहे हैं। किसान अपनी खेतों में पारंपरिक अनाज की जगह फूलों की खेती पर जोर दे रहे हैं और परिवार के सदस्य भी खेती से लेकर माला बनाने तक के काम में जुटे हैं।

देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के कनिया पोखर, मल्हारा और जरिया समेत कई गांवों में

सैकड़ों किसान फूलों की खेती कर रहे हैं। इन गांवों के किसान खेतों में फूल उगाने के साथ-साथ घर पर ही छोटे-छोटे फूलों की माला तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं। इससे किसानों को खेती के साथ माला बिक्री से भी अतिरिक्त आमदनी हो रही है।

किसान प्रमोद पुजहर बताते हैं कि श्रावणी मेला के दौरान फूलों की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान परिवार के साथ मिलकर फूलों की खेती कर रहे हैं और तैयार फूलों से माला बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है।

युवा किसान एमडी दानिश का कहना है कि अनाज और धान की तुलना में फूलों की खेती अधिक मुनाफे वाली साबित हो रही है। खासकर देवघर जैसे धार्मिक शहर में फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। श्रावणी मेले के दौरान मांग और बढ़ जाती है, इसलिए किसान बड़े पैमाने पर फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के उद्यान मित्र सतीश यादव बताते हैं कि देवघर जिले में फूलों के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है। यही वजह है कि किसानों को फूलों की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बेजरा पुल का पिलर धंसा, धनबाद-जामताड़ा के बीच संपर्क प्रभावित

धनबाद, एजेंसी। जामताड़ा और धनबाद जिले को जोड़ने वाले बेजरा पुल का एक पिलर धंस गया है। पुल के पिलर नंबर चार के धंसने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुल की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद करा दिया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से दोनों जिलों के बीच सीधा संपर्क प्रभावित हुआ है।

स्थानीय ग्रामीणों ने पुल के आसपास लंबे समय से जारी बालू उठाव को पिलर के धंसने की प्रमुख वजह बताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी से लगातार बालू निकाले जाने के साथ-साथ बालू लदे भारी वाहनों की आवाजाही से पुल की नींव कमजोर हुई। लोगों का कहना है कि यदि लंबे समय से इस क्षेत्र में बालू का परिवहन जारी था, तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

पिलर धंसने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। पूर्वी टुंडी के अंचलाधिकारी सुरेश प्रसाद बर्नवाल और जामताड़ा के अंचलाधिकारी अभिश्वर मुर्मू ने पुल का जायजा लिया। इसके अलावा धनबाद

के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे और पुल की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण किया।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जुगुड़ी घाट से नाव के जरिए लगातार बालू निकाले जाने की शिकायत मिलती रही है। आरोप है कि पुल के आसपास बड़े पैमाने पर बालू हटाए जाने से नदी की प्राकृतिक सतह प्रभावित हुई, जिसका असर पुल के पिलर और उसकी नींव पर पड़ा। वहीं, बालू लदे ट्रैक्टर और हाईवा के लगातार गुजरने से पुल पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की बात भी ग्रामीणों ने कही है।

अधिकारियों के अनुसार, पुल पहले से ही काफी क्षतिग्रस्त स्थिति में था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जेसीबी की मदद से रास्ते को तत्काल ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्ष भी पुल पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन रात के समय असामाजिक तत्वों ने बैरिकेडिंग हटा दी थी। बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी संबंधित लोगों के मौके से भाग जाने की बात सामने आई है।

एनजीटी की पाबंदी के बावजूद क्षेत्र में कथित तौर पर जारी बालू उठाव और परिवहन ने खनन विभाग, परिवहन विभाग तथा स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते अवैध बालू उठाव पर रोक लगाई जाती और पुल की नियमित निगरानी होती, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।

पुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से इसकी तकनीकी जांच कराने की तैयारी की जा रही है। निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। साथ ही पिलर के आसपास बालू उठाव पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत बताई जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से बेजरा पुल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। धनबाद से जामताड़ा की ओर जाने वाले लोगों को फिलहाल कासजोड़ और करमदाहा होकर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स वार्षिक चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज, 13 सितंबर 2026 को मारवाड़ी भवन में होगा मतदान

रांची, एजेंसी। व्यवसायियों का प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव 13 सितंबर 2026 को मारवाड़ी भवन, हरमू रोड, रांची में आयोजित होगा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर आज चैंबर भवन में चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनाव कार्यक्रम एवं नामांकन प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करते हुए नामांकन दाखिल करने एवं नामांकन वापस लेने की तिथियां निर्धारित की गई। चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर ने बताया कि चुनाव में भाग लेने के इच्छुक प्रत्याशी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके पश्चात प्राप्त नामांकनों की स्क्रूटिनी की जाएगी तथा प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चैंबर की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के साथ-साथ छह प्रमंडलों के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्षों का भी होगा चुनाव। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए आमसभा से 21 दिन पूर्व सदस्यों को नोटिस निर्गत करने की बाध्यता है जिसके तहत आज चैंबर कार्यालय द्वारा सभी सदस्यों को आगामी आमसभा एवं चुनाव से संबंधित नोटिस निर्गत कर दी गई है। चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर ने बताया कि ऐसे सदस्य, जिन्हें चैंबर की सदस्यता प्राप्त किए हुए एक वर्ष पूर्ण हो चुका है।

संक्षिप्त समाचार

बेटी और पोते ने बूढ़ी मां के साथ की 14 लाख की ठगी, पटना हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

पटना, एजेंसी। एक बूढ़ी महिला के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर चौदह लाख रुपए निकालने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने उस महिला की बेटी और पौत्र को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस राजीव राय की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। बूढ़ी महिला के बैंक खाते से उसकी बेटी और पौत्र ने तीर्थ यात्रा के नाम पर चौदह लाख रुपए धोखा दे कर निकाल लिए, जब उस बूढ़ी महिला को इस बारे में पता चला, तो उसने बैंक खाते में शून्य अकाउंट होने की शिकायत दर्ज कराई। उसकी बेटी और पौत्र ने गिरफ्तार होने की आशंका से पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि बूढ़ी महिला अपने पति के पेंशन पर निर्भर थी। पर इस धोखाधड़ी के कारण अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने को मजबूर हो गयी। कोर्ट ने कहा कि जो महिला अपने पति के पेंशन से अपना जीवन यापन कर रही थी, अपने दैनिक खर्च के लिए अपने बेटा बेटी पर रहने को मजबूर हो गई। कोर्ट ने इसी आधार पर अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत से याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस आरोपी बेटी और पौत्र को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। मामले की शिकायत पर पुलिस कभी भी एक्शन ले सकती है।

भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार, एके-47 केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एके 47 राइफल बरामदगी मामले में बड़ी गिरफ्तारी की है। एनआई के अनुसार, 19 अगस्त को मामले में फरार चल रहे आरोपी भैरव त्रिपाठी को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज का रहने वाला है। भैरव त्रिपाठी ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर नगालैंड के दीमापुर से प्रतिबंधित हथियार बिहार लाने की साजिश रची थी। एजेंसी अब उससे हथियारों की खरीद-बिक्री, फंडिंग और उसके गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं, 5 जुलाई 2024 को मुजफ्फरपुर जंक्शन से विकास कुमार और सत्यम कुमार को एके-47 के लेंस और बट के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया था कि वे दीमापुर से हथियारों की खेप लाकर बिहार में बेचते थे। जांच में पूर्वी चंपारण के मधुबन निवासी मोहम्मद अहमद अंसारी का नाम सामने आया, जिस पर हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि विकास कुमार ने फकुली थाना क्षेत्र के मनकौली निवासी मुखिया के पुत्र देवमणि कुमार को एके-47 बेची थी। इसके बाद पुलिस ने मनकौली श्मशान घाट से एके-47 और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए थे। एजेंसी ने 8 मई 2025 को विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2026 को मंजूर खान और 15 अप्रैल 2026 को कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया।

महिला है या जल्लाद! जान निकलने तक दबाती रही गला फिर पैर पकड़कर घुमाते हुए खेत में फेंका 5 वर्षीय बच्ची का शव

चंपारण, एजेंसी। बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बगहा से विचलित करने वाली खबर आई है।यहां धाना थाना क्षेत्र में बुधवार को एक खेत से करीब पांच वर्षीय बच्ची का शव पाया गया है। घटना तमकुही चौक के पास बजाज एजेंसी के सामने दक्षिण दिशा में स्थित खेत की है। बच्ची की पहचान अभी नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना: मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने खेत में बच्ची का शव देखा और इसकी सूचना धनहा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच कर घेराबंदी की। स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार रात करीब 10 बजे एक महिला को बच्ची के साथ जाते देखा गया था। प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि महिला बच्ची के साथ मारपीट कर रही थी। पुलिस अब महिला की पहचान और उसके संबंध में जानकारी जुटा रही है।सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बच्चे का गला दब कर फेंकती हुई नजर आ रही हैं। वहीं थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया है कि घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है साथ ही फोरेंसिक टीम को सूचना दे दी गई है।पुलिस आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को भी खंगाल रही है ताकि मंगलवार रात बच्ची के साथ महिला की पहचान की जा सके। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है लोगों का कहना है कि यदि बच्ची के साथ मारपीट की सूचना समय पर पुलिस को दी जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। पुलिस फिलहाल बच्चे की पहचान करने तथा घटना के कर्म और पूरे मामले की जाँच में जुटी है।पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी महिला बच्ची की मां है या कोई अन्य। सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है की महिला ने पहले आस-पास देखा फिर बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके पैर पड़कर घुमाते हुए गन्ने के खेत में फेंक दिया।

भारत की लाइफलाइन 'चिकन नेक' पर अमित शाह की पैनी नजर,

किशनगंज के अधिकारियों के साथ महामंथन

किशनगंज, एजेंसी। बिहार के किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के तीन दिवसीय दौरे से जिले में हलचल तेज हो गई है। वह 20 से 22 अगस्त तक दौरे पर हैं। शाह सुरक्षा मामलों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर विशेष चर्चा हुई है। इसमें किशनगंज भी आता है, जिसकी सीमा नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ी है। बता दें कि निकटवर्ती पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक महीने में यह दूसरा दौरा है।

चिकन नेक की सुरक्षा पर मंथन

सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ बीरेन दुबे ने गृह मंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को चिकन नेक की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम बताया है। इस दौरे के मद्देनजर किशनगंज से लगी भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षात्मक गतिविधियां बढ़ गई हैं। सीमा पर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत-नेपाल सीमा जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक विशेष बैठक का आयोजन भी किया गया है।

द्विपक्षीय सुरक्षा समन्वय समिति बैठक

इस समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक ठाकुरगंज स्थित सशस्त्र सीमा बल की 19वीं वाहिनी के प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में किशनगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उनके साथ नेपाल के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा एवं दोनों देशों में बेहतर

तालमेल बनाना था। डीएम नवीन कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बैठक की जानकारी दी है।

अवैध गतिविधियों पर कड़ा पहरा

इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा मादक पदार्थों और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी रोकने और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्रवाई पर सहमति बनी। दोनों देशों की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान करने और आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

आपातकालीन समन्वय और प्रभावी निगरानी

इसके अतिरिक्त, सीमा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सीमा पार अपराधों की रोकथाम पर चर्चा हुई। संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने और आपात स्थिति में त्वरित समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल मजबूत करना था, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे।

बैठक में उपस्थित मुख्य अधिकारी

बैठक में किशनगंज के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मौजूद रहे। वहीं नेपाल की ओर से झापा के प्रमुख जिला अधिकारी शिवराम गेलल और मोरंग के प्रमुख जिला अधिकारी युवराज कटेल शामिल हुए। इनके अलावा नेपाल पुलिस के पुलिस अधीक्षक तथा सशस्त्र पुलिस बल के पदाधिकारियों सहित दोनों देशों के अन्य कई संबंधित अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित रहे।

क्या है चिकन नेक?

'चिकन नेक' के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल का सबसे रणनीतिक भूभाग माना जाता है। इसकी चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से में महज 20 किलोमीटर के आसपास है। यह संकरा मार्ग भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है। यही मुख्य वजह है कि पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इस गलियारे को भारत की सामरिक जीवनरेखा मानते हैं।

8वीं पास से बीटेक तक, 1000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का मौका, 20 नियोजक देंगे नियुक्ति पत्र

खगड़िया, एजेंसी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार बनने के बाद एक करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अब सम्राट सरकार इस लक्ष्य को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है और राज्यभर में रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है।

खगड़िया में पहले चरण का सबसे बड़ा मेला: इसी कड़ी में खगड़िया जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां 31 अगस्त को एक हजार से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए पहले चरण का सबसे बड़ा और पहला रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह साल का दूसरा रोजगार मेला होगा।

कोशी कॉलेज मैदान में होगा आयोजन: जिला नियोजन पदाधिकारी अंकिता ने बताया कि युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा जिला नियोजनालय, खगड़िया की ओर से कोशी कॉलेज के मैदान में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 20 से अधिक निजी क्षेत्र के नियोजक युवाओं के चयन के लिए पहुंचेंगे। 'इस रोजगार मेले में कुल एक हजार से अधिक पदों पर युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी एक ही जगह पर अलग-अलग कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा

बड़ी कंपनियां लगाएंगी स्टॉल: रोजगार मेले में जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत फाइनेंस, ब्लिंकिट, एलएंडटी, एयरटेल पेमेंट बैंक और एसआईएस समेत कई प्रमुख कंपनियों के स्टॉल मौजूद रहेंगे। युवाओं को अलग-अलग सेक्टर में उपलब्ध पदों के अनुसार चयन का मौका मिलेगा।

एक हजार से अधिक पदों पर भर्ती का लक्ष्य: जिला नियोजनालय के अनुसार इस मेले में कुल एक हजार से अधिक पदों पर युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। एक ही जगह पर कई कंपनियों में आवेदन और चयन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

आईजी विकास वैभव तक पहुंचा भैंस विवाद, आरजेडी नेता की शिकायत के बाद एसपी को जांच के निर्देश

गया, एजेंसी। बिहार के गया में एक भैंस के गायब होने और फिर उसके मिलने के घटनाक्रम के बीच कई मोड़ आए। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया है। अतरी विधानसभा से राजद के पूर्व विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव गुरुवार को मगध रेंज आईजी विकास वैभव से मिले। इसके बाद आईजी ने गया ग्रामीण एसपी को जांच के निर्देश दिये हैं।

समझिये क्या है पूरा मामला?: दरअसल, यह मामला एक भैंस से जुड़ा है। करीब सप्ताह भर पहले अतरी क्षेत्र के रहने वाले सूरज यादव की भैंस गुम हो गई थी। इससे पूरा परिवार परेशान था। काफी खोजबीन की गयी तो एक महादलित के घर उनकी भैंस बंधी मिली। इसके बाद सूरज यादव अपना भैंस बताकर घर ले आए।

भैंस को थाने में बांधा: इसके बाद जिसने भैंस को बांधे रखा था, वह थाना पहुंच गया। उसने भैंस के मालिकाना हक की दावेदारी की। सूरज यादव को भी थाना बुलाया गया। दोनों पक्ष में पहले बात शुरू हुई। इसके बाद धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया। इसके बाद अतरी थाना की पुलिस ने सूरज यादव के घर से भैंस को लाकर थाने में बांध दिया। दो दिनों तक भैंस थाने में रही।

पुलिस ने वापस की भैंसः पुलिस द्वारा भैंस को थाना लाने का मामला आग की तरह फैल गया। इसी दौरान एक सोशल मीडिया कंटेट क्रिएटर थानाध्यक्ष से सवाल करने लगा। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तुरंत जांच -पड़ताल की। कार्रवाई को बढ़ाते हुए भैंस को उसके वास्तविक

मालिक सूरज यादव को सौंप दिया गया।

भैंस का मामला एससी-एसटी तक पहुंचा: मामला यहीं ठंडा नहीं हुआ। सूरज यादव की गुम भैंस जिस महादलित के घर में मिली थी, उसके द्वारा सूरज यादव पर एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया गया। इस केस की पुष्टि अतरी के पूर्व विधायक अजय यादव उर्फ़ रंजीत यादव ने की है। विधायक ने कहा कि यह सब नाजायज हो रहा है। इसके बाद वे आईजी विकास वैभव के पास पहुंच गए।

'मगध रेंज आईजी विकास वैभव से मिले। विवाद से जुड़े सभी पहलूओं को उनके समक्ष रखा। अतरी थानाध्यक्ष की शिकायत की है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बालू में बेईमानी की। कई तरह के ऐसे काम किया, जो ठीक नहीं है, हमने सारे सबूत आईजी मगध रेंज विकास वैभव को दे दिए हैं।'

'जितना केस लड़ेगा, उतने भैंस आ जाएगी': पूर्व विधायक ने बताया कि 'बताइए भैंस के विवाद में वह जितना केस लड़ेगा, उतना में भैंस ही खरीद लेता। हैरानी की बात है कि जिस सोशल मीडिया कंटेट क्रिएटर ने थानाध्यक्ष से सवाल किया, उसपर भी थानाध्यक्ष अजय कुमार ने केस दर्ज कर दिया है। पूर्व विधायक ने थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाया है।

वर्तमान विधायक पर आरोप: एक भैंस के विवाद में मामले में जमकर राजनीतिकरण हो रहा है। भैंस के कथित असली मालिक सूरज यादव ने इस मामले में विवाद उत्पन्न में अतरी के वर्तमान विधायक का हाथ होने की भी आशंका जताई है। फिलहाल अब ग्रामीण एसपी की जांच के बाद ही यह सामने आएगा।

जांच के बाद होगा खुलासा: किसने क्या किया, किसकी क्या और कहां गलती थी, फिलहाल भैंस विवाद का मामला बिहार में चर्चित मामला बन गया है। क्योंकि, एक भैंस के मालिकाना हक की दावेदारी के बीच उत्पन्न अलग-अलग हालातो के कारण चार विवाद उत्पन्न हो गए हैं।

बिहार को मिली एक और अमृत भारत ट्रेन

भागलपुर-अहमदाबाद के बीच चलेगी, इन स्टेशनों पर ठहराव

मुंगेर, एजेंसी। बिहार के भागलपुर को अहमदाबाद से जोड़ने वाली रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए रेलवे ने 19423/19424 अहमदाबाद-भागलपुर-अहमदाबाद साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन का निर्णय लिया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और बिहार के पूर्वी हिस्से को गुजरात के प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र से जोड़ने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।

इन यात्रियों को मिलेगी गुजरात की सीधी रेल सुविधाः पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि यह ट्रेन वर्तमान में चल रही 09447/09448 अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद क्लोन स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन को नियमित करते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित की जाएगी। इससे भागलपुर समेत मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को गुजरात की सीधी रेल सुविधा मिलने से काफी लाभ होगा।

26 अगस्त से शुरू होगी सेवा: सीपीआरओ शिबराम मांझी ने बताया कि 19423 अहमदाबाद-भागलपुर साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद से शाम 6:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन 26 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी और तीसरे दिन सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

भागलपुर से ट्रेन का समय: वहीं वापसी में 19424 भागलपुर-अहमदाबाद साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर से शाम 4:45 बजे रवाना होगी। इसकी सेवा 28 अगस्त 2026 से शुरू होगी और तीसरे दिन सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

इन तीन जगहों पर होगा ठहराव: सीपीआरओ ने बताया कि इस नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस का पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले मार्ग में अभयपुर, जमालपुर और सुल्तानगंज स्टेशनों पर ठहराव निर्धारित किया गया है। इससे मुंगेर जिले के यात्रियों के साथ-साथ लखीसराय, भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी अहमदाबाद की सीधी रेल सेवा का लाभ मिलेगा।

व्यापार और रोजगार के लिए अहम कनेक्टिविटी: सीपीआरओ ने कहा कि भागलपुर को 'भारत की सिल्क सिटी' के नाम से जाना जाता है और यह बिहार का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। दूसरी ओर अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र है। दोनों शहरों के बीच सीधी साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के नियमित परिचालन से व्यापार, रोजगार, शिक्षा और आवागमन के क्षेत्र में यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है।

ढाई साल के मासूम बेटे की हत्या, दादा ने कहा- 'मां ने बिस्किट में जहर खिलाया'

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर हरि थाना क्षेत्र के टेंगरांहा उत्तरी टोला में ढाई वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने उसकी मां पर बिस्किट में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाने का आरोप लगाया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

बच्चे के पिता पंजाब में करते हैं मजदूरी: मृतक की पहचान टेंगरांहा उत्तरी टोला निवासी अखिलेश राम के पुत्र आर्यन कुमार के रूप में हुई है। बच्चे के पिता पंजाब में मजदूरी करते हैं। मृतक के दादा कैलाश राम के अनुसार करीब सात वर्ष पहले अखिलेश की शादी आरती कुमारी से हुई थी। दोनों के बीच अक्सर

पारिवारिक विवाद होता था और महिला कई बार बिना बताए मायके चली जाती थी।

दादा-दादी का बच्चे की मां पर आरोप: बच्चे के दादा ने बताया कि 'करीब 15 दिन पहले आरती मायके गई थी और बुधवार शाम ही वापस लौटी थी। गुरुवार दोपहर बच्चे के मैं और मेरी पत्नी मजदूरी करने घर से बाहर गए थे। इसी दौरान आरती ने बिस्किट में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर बेटे आर्यन को खिला दिया। कुछ देर बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। '

पुलिस और एफएसएल की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही रामपुर हरि थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया। टीम ने मौके से विभिन्न नमूने एकत्र किए। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है।

क्या कहते हैं थानाध्यक्ष: रामपुर हरि थानाध्यक्ष अंजली कुमारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्चे की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होने की आशंका है। मामले में बच्चे की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों से लिखित आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मातम में बदली खुशियां, जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद मां की मौत

मोतिहारी, एजेंसी। बिहार के मोतिहारी में में प्रसव के बाद एक 22 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान चहिलाहा कटहरिया, वार्ड नंबर-11 निवासी अरविंद कुमार की पत्नी विनीता कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार विनीता की शादी साल 2021 में हुई थी। प्रसव के लिए उसे 18 अगस्त 2026 को एक क्लिनिक में भर्ती कराया गया था।

महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया था जन्म: महिला के देवर दीपेश कुमार का कहना है कि 19 अगस्त को विनीता ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। प्रसव के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद विनीता की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रसव के बाद मरीज की उचित देखरेख और इलाज नहीं किया गया, जिसके कारण उसकी हालत लगातार खराब होती चली गई।

डॉक्टर पर उचित इलाज नहीं करने का आरोप: मृतका के देवर दीपेश कुमार ने क्लिनिक में मरीज की देखरेख को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्रसव के बाद विनीता की स्थिति बिगड़ने के बावजूद समय पर उचित इलाज और निगरानी नहीं की गई। परिवार का कहना है कि अगर समय रहते बेहतर चिकित्सा सुविधा और आवश्यक उपचार मिलता, तो शायद विनीता की जान बचाई जा सकती थी।

परिजनों ने की कार्रवाई की मांग: महिला की मौत की वास्तविक वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों की ओर से लगाए गए लापरवाही के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है। घटना के बाद परिवार ने पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।

क्या कहती है पुलिस?: नगर थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। महिला की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

शेरशाह सूरी मकबरा तालाब में मरीं 8 से 10 क्विंटल मछलियां

सासाराम, एजेंसी। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरा परिसर स्थित तालाब में भारी संख्या में मछलियों की मौत हो गई है। तालाब में एक साथ बड़ी संख्या में मछलियों के मरने से जहां मछली पालने वाले संवेदक को लाखों रुपये के नुकसान का दावा किया जा रहा है, वहीं तालाब के दूषित पानी को लेकर मकबरा घूमने आने वाले पर्यटकों की परेशानी भी बढ़ गई है।

शेरशाह सूरी मकबरा तालाब में मछलियां मरीं: मकबरा परिसर के तालाब में पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में मछलियां मृत अवस्था में पानी के ऊपर तैरती दिखाई दे रही हैं। मछलियों की मौत के बाद तालाब के आसपास दुर्गंध भी फैलने लगी है। इससे पर्यटकों और आसपास मौजूद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

8 से 10 क्विंटल मछलियां मर गईं: तालाब में मछली पालन का काम करने वाले संवेदक दीना चौधरी ने बताया कि इस बार करीब 8 से 10 क्विंटल मछलियां मर गई हैं। उन्होंने मरी हुई मछलियों की कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपये बताई है। उनका कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब मकबरा के तालाब में इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई है। पिछले करीब छह महीने पहले भी बड़ी संख्या में मछलियां मर गई थीं।

संवेदक का आरोप: दीना चौधरी ने बताया कि बीते एक साल में तीन से चार बार तालाब में मछलियों के मरने की

घटना हो चुकी है। बार-बार मछलियों की मौत होने से मछली पालन करने वाले लोगों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मछुआरा संवेदक का कहना है कि तालाब में पहले पानी की निकासी और साफ पानी के आने की व्यवस्था थी। नहर के माध्यम से तालाब में साफ पानी पहुंचता था, जबकि तालाब का गंदा पानी बाहर निकल जाता था लेकिन पिछले कई वर्षों से यह सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ा है।

'पानी के लिए दरखास्त दिए थे लेकिन पानी नहीं आया। चार-पांच बार मछली मर चुकी है। फिर से गंदा पानी के कारण फिर से मछली मर गई। चार से पांच की मछली मर गई है। सिंचाई विभाग को भी आवेदन दिए हैं लेकिन पानी नहीं छोड़ा जा रहा है

क्यों हो रही मछली की मौत?: ऐसे में तालाब में लगातार गंदा पानी जमा हो रहा है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण तालाब का पानी दूषित होता जा रहा है। इसी दूषित पानी में मछलियों के रहने से उनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। संवेदक का कहना है कि अगर पानी के आने और गंदे पानी की निकासी की पुरानी व्यवस्था को फिर से चालू कर दिया जाए तो इस समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

क्या बोले जानकार?: वहीं, इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहायक संरक्षक अमृत झा ने फोन पर बताया कि पानी फिल्टर नहीं होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा, 'तालाब के पानी की समुचित सफाई और फिल्ट्रेशन नहीं होने से पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर तालाब में मौजूद मछलियों पर पड़ रहा है।'

दुर्गंध से पर्यटक परेशान: शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम की ऐतिहासिक पहचान होने के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में मकबरा परिसर के तालाब में बार-बार मछलियों के मरने और पानी दूषित होने की समस्या गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पर्यटकों का कहना है कि ऐतिहासिक स्थल पर साफ-सफाई और पर्यावरण व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने के बाद पानी से आने वाली दुर्गंध और गंदगी के कारण यहां आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।

संक्षिप्त समाचार

24 घंटे से बिजली न आने से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी, लाइनमैन को बंधक बनाया

कानपुर, एजेंसी। शुक्लागंज के मिश्रा कॉलोनी मछली गेट के पास रखा ट्रांसफार्मर बुधवार रात 11 बजे खराब हो गया था। गुरुवार रात 11 बजे तक दूसरा ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी बिजली आपूर्ति चालू न होने पर क्षेत्रीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही लाइनमैन को बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पब्लिक को शांत कर लाइनमैन को छुड़ाया इसके बाद बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर मरम्मत करने का काम शुरू कराया।

पूर्वोत्तर रेलवे ने पहली बार तीन मालगाड़ियों को जोड़कर चलाई अवध महाशक्ति फेट ट्रेन

लखनऊ, एजेंसी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने माल परिवहन को अधिक कुशल व मजबूत बनाने के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। थ्री इन वन फेट ट्रेन अवध महाशक्ति को गोंडा से मुरादाबाद तक चलाया गया। इस ट्रेन को तीन मालगाड़ियों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक डॉ. शिल्पी कन्नौजिया के नेतृत्व में पूर्वोत्तर रेलवे की पहली %%अवध महाशक्ति%% फ्रेट ट्रेन का सफल संचालन किया गया। गोंडा डिपो की ओर से तैयार इस ट्रेन में कुल 129 वैगन और तीन इंजन लगे थे। इस पहल से रेलवे की परिवहन क्षमता और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तीन गाड़ियों को एक साथ चलाने से समय, ईंधन और मानव संसाधन की बचत होगी। साथ ही ट्रैक क्षमता का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। अलग-अलग ट्रेनें चलाने के बजाय एक ही ट्रिप में अधिक माल की ढुलाई होने से ग्राहकों को तेज और किफायती सेवा मिलेगी। डीआरएम ने इसे मंडल के विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट तालमेल और प्रबंधन का परिणाम बताया।

सात राज्यों के सीएम, मंत्री और तीन देशों के राजदूत होंगे शामिल ; योगी मुख्य अतिथि

वाराणसी, एजेंसी। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) का 56वां वार्षिक सम्मेलन अनंत काशी शुक्रवार से शुरू हो रहा है। तीन दिनों तक नदेसर स्थित ताज में आयोजित इस सम्मेलन में छह से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री के अलावा तीन देशों श्रीलंका, लाओस व थाईलैंड के राजदूत भाग लेंगे। देशभर से एक हजार से अधिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। इस दौरान बनारस के सांस्कृतिक, कला और संस्कृति की विरासत को सहेजने वाले 14 पद्म और भारत रत्न सम्मान प्राप्त कलाकारों और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। एफएचआरएआई के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को छावनी स्थित एक होटल में पत्रकारों को बताया कि पर्यटन मंत्रालय के सहयोग और उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। विशिष्ट अतिथियों में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खूंटे के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश के मंत्री व पर्यटन मंत्री हिस्सा लेंगे। इंडियन होटल्स कंपनी के एमडी एवं सीईओ पुनीत छटवाल, आईटीसी होटल्स के एमडी अनिल चड्ढा, रेडिसन, हिल्टन, आईएचजी और लेमन ट्री जैसी वैश्विक हॉस्पिटैलिटी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि तीन दिनों तक 11 सत्र चलेंगे। इसमें आध्यात्मिक एवं वेलनेस पर्यटन, एमआईसीई, वेडिंग डेस्टिनेशन, सतत हॉस्पिटैलिटी, एआई व डिजिटल परिवर्तन, ओडीओपी-ओडीओसी से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने कहा कि यह सम्मेलन विरासत और नवाचार को जोड़कर भारत के पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

शासन का बड़ा फैसला, अब शहीद परिवार की मेधावी, दिव्यांग छात्राओं को 10 प्रतिशत कम अंक पर भी स्कूटी

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश में उच्च शिक्षा में छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू की जा रही है। योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। सामान्य मेधावी छात्राओं के लिए निर्धारित मेरिट से 10 फीसदी कम अंक पाने वाली शहीद परिवार की मेधावी, दिव्यांग और निराश्रित छात्राएं भी पात्र होंगी। इसके लिए छात्राओं का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल की ओर से जारी दिशानिर्देश के तहत शहीद परिवार में सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों में स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त कमीशन अधिकारी व सैनिक, जो कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए हों, शामिल हैं। अविवाहित शहीद सैनिक की मां और अविवाहित बहन को आश्रित माना जाएगा। योजना में उच्च शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के राज्य और निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय, एडेड और स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शामिल होंगे। पोर्टल लाइव होने के एक सप्ताह में विश्वविद्यालय पात्र छात्राओं की सूची संबंधित डीएम और निदेशक उच्च शिक्षा को भेजेंगे। डीएम सत्यापन के बाद चयनित वेंडर से स्कूटी आवंटित कराएंगे और वितरण के बाद प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड करेंगे। दिव्यांग श्रेणी में मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से ग्रस्त ऐसी छात्राएं पात्र होंगी, जिनका कमर से ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो और वे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल स्वयं चला सकें। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को उनकी दिव्यांगता 80 फीसदी या उससे अधिक प्रमाणित करनी होगी। इन्हें स्कूटी के साथ रेट्रोफिटेड स्टेबलाइजर किट भी मिलेगी। वहीं, निराश्रित श्रेणी में वे छात्राएं होंगी, जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो और परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई सदस्य न हो। परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये तक होने पर छात्राएं योजना में शामिल होंगी। स्कूटी पैकेज में पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, आईएसआई मार्का हेलमेट, चार लीटर पेट्रोल और पूरी एसेसरीज शामिल होगी।

पांच साल में 20 लोगों की चली गई जान, सो रहे हैं जिम्मेदार

बारिश में बढ़ जाता है खतरा

आगरा, एजेंसी। बारिश का पानी निकालने के लिए बनाए गए नाले जिम्मेदारों की लापरवाही से जानलेवा साबित हो रहे हैं। खुले और बदबूदार नाले बीते पांच वर्षों में 20 लोगों की जान ले चुके हैं। 20 फीट तक गहरे और खुले पड़े नाले सीधे तौर पर मौत के कुएं बन चुके हैं। कोई घर के सामने खेलते हुए गिरा तो कोई बाजार से लौटते हुए।

हर बारिश में खुले नालों का खौफनाक मंजर उन लोगों को डराता है जो गिरने के बाद जैसे-तैसे बच सके। राजपुर चुंगी पर पांच बाइक सवारों के डबल पेट्रोल पंप नाले में गिरने की घटना के बाद नालों को ढकने की मांग तेज हो गई है।

चोक पड़े गहरे नाले में गिरकर हाल में ही सुभाष बाजार में गंगा देवी की मौत हो गई थी। शहर में 410 छोटे-बड़े नाले हैं जिनमें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मंटोला, महावीर नाला, भैंरो नाला समेत 18 नाले 20 फीट तक गहरे हैं। बारिश में पानी में डूबी सड़कों और नालों के बीच का फर्क खत्म हो जाता है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। राजपुर चुंगी और सुभाष बाजार जैसे हादसे अफसरों की संवेदनहीनता बयां करते हैं। हादसों के शिकार लोगों का कहना है कि इन नालों को आरसीसी स्लैब या लोहे के जाल से ढका नहीं गया तो और जिंदगियां जाएंगी।

पार्षदों ने भी उठाई मांग : भाजपा पार्षद दल के उपनेता प्रकाश केसवानी ने कहा कि नालों में गिरकर कई जानें जा चुकी हैं। गहरे नालों को सबसे पहले ढका जाए। ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। वहीं बसपा पार्षद दल के नेता कप्तान सिंह ने बताया कि राजपुर चुंगी पर जिस तरह से बाइक सवार गिरे, उसे देखते हुए गहरे नाले तत्काल ढके जाएं। नगर निगम में इसका प्रस्ताव लाएंगे।

स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा बुरा प्रभाव : नालों के किनारे शहर के पांच लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉ. यतेंद्र चाहर ने बताया कि खुले नालों के किनारे रहने वाले लोगों को त्वचा रोग के साथ सीवर के कारण उठने वाली दुर्गंध से सांस संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं। क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से एलर्जी, संक्रामक रोग का भी खतरा रहता है।

एसएन मेडिकल कॉलेज में दवाओं का टोटा, पर्चे की आधी दवाएं भी नहीं मिल रहीं

आगरा, एजेंसी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बच्चों के दवाओं की भारी कमी है। ओपीडी में पर्चे पर लिखी दवाओं में से आधे से भी कम मिल रही हैं। तीमारदारों का आरोप है कि काउंटर से सस्ती दवाएं ही मिल रहीं, महंगी खरीदनी पड़ रही हैं। इससे पैसा अधिक खर्च हो रहा है, परेशानी भी हो रही है।

बाल रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 200 से अधिक बच्चे आ रहे हैं। इसमें वायरल फीवर, मिर्गी, पेट रोग, डायरिया, फूड पॉइजनिंग की परेशानी के अधिक हैं। यहां कैल्शियम, मल्टीविटामिन, मिर्गी, पेट रोग समेत अन्य मर्ज की दवाओं की कमी है। सिरप का भी टोटा है। पर्चे पर लिखी दवाएं पूरी नहीं मिलने पर तीमारदार इनको खरीद रहे हैं। लंबे समय से दवाओं की कमी चल रही है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम (यूपीएमएससीएल) को मांग भेजी जा चुकी है। आवक में देरी हो रही है। इसी सप्ताह से जरूरी दवाएं प्राप्त होने लगेंगी।

ये बोले तीमारदार

चार में से एक ही दवा मिली : सिकंदरा के राकेश कुमार ने बताया कि वह बेटी को दिखाने एसएन में आए। डॉक्टर साहब ने चार दवाएं लिखी, एक ही मिली है, बाकी की तीन खरीदनी पड़ेंगी।

दौरे का सिरप नहीं, 400 का खरीदा

मोती महल की पूजा ने बताया कि उसके बच्चे को मिर्गी का दौरा आता है। यहां आधी दवाएं ही मिल रही हैं। एक सिरप 400 का आता है, वह हर बार खरीदना पड़ता है।

600 रुपये की खरीदी दवा

जलेसर के शैलेंद्र ने बताया कि भतीजी को दिखाने आया हूं। आंत की बीमारी है। पूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। पिछली बार 600 रुपये की दवाएं खरीदनी पड़ी।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 57 अधिकारी रेलवे में देंगे सेवाएं

लखनऊ, एजेंसी। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान (इरिटम) में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 57 अधिकारी अब रेलवे में सेवाएं देंगे। बृहस्पतिवार को इरिटम परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में अधिकारी प्रशिक्षुओं ने व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा और समर्पण की शपथ ली।

इरिटम के प्रो. कृष्णा तिवारी ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि रेलवे के महानिदेशक रंजन प्रकाश ठाकुर रहे। डीन शिशिर सोमवंशी ने अधिकारी प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई। पाठ्यक्रम निदेशक पीपी लाठे ने प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपर महानिदेशक संजय त्रिपाठी ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महानिदेशक रंजन प्रकाश ठाकुर ने अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन करने और यात्रियों के हित में समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। इस दौरान इरिटम ध्वज का हस्तांतरण भी किया गया। यह संस्थान की परंपराओं, मूल्यों और विरासत को आगे बढ़ाने का प्रतीक है।

प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी प्रशिक्षुओं को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। डॉ. आकांक्षा झा को महानिदेशक का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु पुरस्कार मिला। उत्कर्ष त्रिपाठी को दल भावना और अभय दीप सिंह को सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में आकांक्षा गुप्ता और राजेश कुमार व खेलकूद में पूर्णिमा सूदेन और भारत पाल सिंह को सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु चुना गया।

बिना बिल-फोटो के 1.51 करोड़ का भुगतान, पोर्टल पर अपलोड मिले रफ कागजात, जांच के आदेश

कानपुर, एजेंसी। कानपुर में भीतरगांव क्षेत्र पंचायत में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकास कार्यों के नाम पर करीब 1.51 करोड़ रुपये के भुगतान ने सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कई कार्यों में निर्धारित स्वीकृति प्रक्रिया का पालन किए बिना भुगतान कर दिया गया।

इतना ही नहीं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज कई कार्यों में बिल और कार्य की फोटो के बजाय मेजरमेंट बिल (एमबी) और टीडीएस कटौती के नाम पर रफ टीडीएस कैलकुलेशन रिपोर्ट की फोटो अपलोड की गई है। क्षेत्र पंचायतों में राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि से विकास कार्य कराए जाते हैं।

बिल और फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होता है : नियमानुसार 10 लाख रुपये से अधिक के कार्यों के प्रस्ताव पर डीपीआरओ, सीडीओ और आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी स्तर से स्वीकृति के बाद ही काम कराया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद बिल और फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होता है। जांच के बाद लेखाकार और खंड विकास अधिकारी की निगरानी में भुगतान होता है।

विभागीय अधिकारियों में हड़कंप : लेकिन भीतरगांव में पोर्टल पर दर्ज कार्यों को देखें, तो कई में 10 लाख रुपये की सीमा पार कर भुगतान किया गया है। यही नहीं कई कार्यों की एक आईडी बनाई गई लेकिन पोर्टल पर भुगतान को दो हिस्सों में बांटकर दर्ज कर दिया। इस खुलासे के बाद से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

10 लाख से अधिक के इन कार्यों का नियम की अनदेखी कर हुआ भुगतान : रसूलपुर जाजपुर में जय सिंह के घर से रामनिवास के घर तक सड़क निर्माण कार्य 10.33 लाख रुपये से कराया गया।

सिहुपुर प्राथमिक विद्यालय के बाहर राजन शुक्ला के घर से सोनेलाल के घर तक डामर सड़क निर्माण कार्य 10.37 लाख रुपये से कराया गया।

कुड़नी में बीएएमए इंटर कॉलेज के बाहर डामर रोड का निर्माण कार्य 11 लाख से अधिक की राशि से कराया गया।

शाखारी में हीरालाल के घर तक सड़क निर्माण कार्य 11.35 लाख रुपये से कराया गया।

बैजूपुर में शिवम के घर से विजय प्रताप के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य 11.39 लाख रुपये से कराया गया।

कुड़नी में अरविंद कुशवाहा के घर से श्रीराम के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य 11.43 लाख रुपये से कराया गया।

शाह गांव में रतिराम के घर से जलिया देवी मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य 14.74 लाख रुपये से कराया गया।

यूपी-जापान साझेदारी को नई ऊंचाई देने के लिए लखनऊ में बनेगी रणनीति, राज्यपाल-सीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए शुक्रवार का दिन अहम होगा। जापानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के तीसरे दिन लखनऊ में व्यापक संवाद होगा। प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट होगी।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निवेश, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, एमएसएमई और महिला सशक्तीकरण पर चर्चा होगी। चार क्षेत्रवार सत्रों में साझेदारी की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। 15 विद्यार्थी अटल विद्यालय का दौरा करेंगे। 15 महिला प्रतिनिधि महिला एवं बाल कल्याण विभाग से मिलेंगी और 1090 महिला हेल्पलाइन का भ्रमण करेंगी। कृषि से एमएसएमई तक चार सत्रों में सहयोग पर मंथन होगा। विधानसभा में समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन सत्र को संबोधित करेंगे।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन पर करार

भारत और जापान ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पर मिलकर काम करेंगे। भारतीय युवाओं को जापान में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बृहस्पतिवार को जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एमओयू किया। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह मौजूद थे।

ताजमहल देख अभिभूत हुए मेहमान

यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पितवार को ताजमहल का दीदार किया। ब्रज की पारंपरिक संस्कृति के तहत मयूर नृत्य और रसिया की प्रस्तुतियों से मेहमानों का स्वागत हुआ।

ताजमहल की बारीक कारीगरी देखकर गवर्नर नागासाकी ने कहा कि तस्वीरों में ताजमहल देखने और सामने से उसकी खूबसूरती महसूस करने का अनुभव बिल्कुल अलग है। यामानाशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष काजुहिको नाकामुरा ने यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं की भी सराहना की।

पुलिस विभाग में देर रात बड़े स्तर पर तबादले, गोंडा-सुल्तानपुर सहित सात जिलों के बदले गए कप्तान

लखनऊ, एजेंसी। डीजीपी मुख्यालय ने बृहस्पतिवार देर रात सात जिलों के पुलिस कप्तान समेत नौ आईपीएस का तबादला कर दिया। गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर का एसपी बनाया गया है। सुल्तानपुर में तैनात चारू निगम को यूपी 112 भेजा गया है।

पुलिस के बल प्रयोग को लेकर विवादों में घिरे मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडेय को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। झांसी के एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिजनौर के एसपी अभिषेक को गोंडा का नया कप्तान बनाया गया है। बलरामपुर के कप्तान विकास कुमार को झांसी का एसएसपी बनाया गया है।

संभल के एसपी केके बिश्नोई को बिजनौर का कप्तान बनाया गया है। बाराबंकी में एएसपी विकास चन्द्र त्रिपाठी को आईपीएस बनने के बाद संभल का एसपी बनाया गया है। इसी तरह आईपीएस बने हरदोई के एएसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह को बलरामपुर का एसपी बनाया गया है।

इस फेरबदल के तहत मेरठ, झांसी, सुल्तानपुर, गोण्डा, बिजनौर, सम्भल और बलरामपुर समेत कई जिलों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रशासनिक कसावट और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में कई जिलों के कप्तानों को बदला गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को मुख्यालय व अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनात किया गया है।

गोरखपुर में नशे की खेप का बढ़ता कॉरिडोर, विदेशी 'ओजी' से लेकर बड़ी खेप तक पकड़ी

गोरखपुर। जिले में नशीले पदार्थों की लगातार हो रही बड़ी बरामदगी बताती है कि यह इलाका सिर्फ नशे की खपत का बाजार नहीं, बल्कि अलग-अलग रूट से आने वाली खेपों के लिए ट्रांजिट कॉरिडोर भी बनता जा रहा है। हाल की कार्रवाई में नेपाल, बिहार और थाईलैंड तक जुड़े स्रोत सामने आए हैं। तस्कर खेप को अलग-अलग वाहनों और डिलीवरी पॉइंट के जरिये आगे बढ़ाते हैं। कई मामलों में स्थानीय खरीदार और सप्लायर अलग-अलग होने की बात जांच में सामने आई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, नवंबर 2025 में चौरीचौरा के दुबियारी पुल के पास एसटीएफ ने 6.35 क्विंटल गांजा पकड़ा था। कार्रवाई में पांच तस्कर गिरफ्तार किए गए थे। जांच में इनके तार बिहार और नेपाल से जुड़े मिले थे। आरोपियों के मोबाइल की जांच में 50 से अधिक संदिग्धों के नाम और नंबर सामने आने की जानकारी भी दी गई थी। इससे नेटवर्क के एक खेप तक सीमित न होकर कई स्तरों पर सक्रिय होने के संकेत मिले थे।

जनवरी 2026 में एकला बांध क्षेत्र में एएनटीएफ ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.025 किलो स्मैक और करीब 770 ग्राम हाइड्रोपोनिक 'ओजी' बरामद किया था। दोनों मादक पदार्थों की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 2.35 करोड़ रुपये बताई गई थी। यह कार्रवाई भी इस बात का संकेत थी कि गोरखपुर में पारंपरिक गांजे के साथ महंगे हाइड्रोपोनिक गांजे की सप्लाई ने जगह बनाई है।

31 मई को गोरखपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास एएनटीएफ ने 770 ग्राम हाइड्रोपोनिक 'ओजी' गांजा बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया था कि विदेशी गांजे की खेप थाईलैंड से देश में लाई गई और कोलकाता व बिहार के रास्ते गोरखपुर पहुंचाई गई थी।

आगरा मेट्रो के लिए पेड़ कटेंगे या बचेंगे? सीईसी ने मांगी नई सूची

आगरा, एजेंसी। आगरा के एमजी रोड के डिवाइडर पर लगे पेड़ों को काटने की अनुमति के मामले में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) से संशोधित सूची मांगी है। पर्यावरणविद् डॉ. शरद गुप्ता की शिकायत पर बीते 30 जुलाई को आगरा आए कमेटी के सदस्यों ने निरीक्षण के बाद यह रिपोर्ट सौंपी है जिसमें मेट्रो निर्माण के बुनियादी ढांचे में हुए बदलावों को जरूरी माना गया है। संशोधित सूची मिलने के बाद सीईसी पेड़ काटने के आवेदन पर अपनी अंतिम सिफारिश भेजेगी।

सीईसी के सदस्य सचिव डॉ. सतीश सी. गर्कोटी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2020 को यूपीएमआरसी को 1,823 पेड़ काटने की अनुमति दी थी। हालांकि, बुनियादी ढांचे में कुछ मामूली बदलाव हुए हैं, जिन्हें सीईसी ने वास्तविक परिवर्तन मानते हुए संशोधित सूची की मांग की है। दूसरी ओर, पावरग्रिड कॉरपोरेशन ने हाईटेंशन लाइन के नीचे आ रहे पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी थी, जिसे सीईसी ने खारिज करते हुए ट्रांसमिशन लाइन का अलाइनमेंट बदलने के निर्देश दिए हैं। कमेटी ने पेड़ों की मार्किंग प्रक्रिया का अलाइनमेंट दोबारा कर 15 दिन के भीतर डीएफओ के माध्यम से सीईसी को सूची भेजने को कहा है। समोगर और प्रकाश नगर पुल की नहीं बताई जरूरत सीईसी ने राज्य सेतु निगम के रहनकला-रायपुर रोड पर समोगर पुल और प्रकाश नगर में प्रस्तावित आरओबी के प्रस्ताव को गैरजरूरी बताया है। 29 जुलाई को सीईसी के निरीक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि समोगर पर प्रस्तावित पुल स्थल से एक किमी. दूर इनर रिंग रोड पर पहले ही पुल बना हुआ है। इस पर ट्रैफिक ही नहीं है। 40 मिनट तक सीईसी की मौजूदगी में एक भी चार पहिया वाहन नजर नहीं आया। इनर रिंग रोड पर बने मौजूद पुल से ही इस क्षेत्र को सेवा दी जा सकती है।प्रकाश नगर आरओबी को भी सीईसी ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा है कि यहां रेलवे लाइन एलिवेटेड है। दो अंडरपास पहले ही मौजूद हैं। ट्रैफिक कम है और उद्यमियों ने आरओबी का विरोध किया है।

आईआईटी रिपोर्ट में प्रकाश नगर पुल को माना जरूरी : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूड़की के विशेषज्ञों ने नुनिहाई औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित रेल ओवर ब्रिज को जरूरी बताया है। आईआईटी की रिपोर्ट सीईसी से एकदम अलग है। सीईसी ने पुल को गैरजरूरी माना है, जबकि आईआईटी रूड़की ने आरओबी निर्माण को ट्रैफिक और उद्योग के लिए जरूरी बताया है। आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 400 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी सड़क है। ओवरब्रिज के सुपरस्ट्रक्चर के नीचे न्यूनतम क्लीयरेंस 6.898 मीटर है जो मानक 5.50 मीटर से अधिक है। इससे ओवरलोडेड और भारी वाणिज्यिक वाहन बिना किसी रुकावट के गुजर सकेंगे। ट्रेलर मुड़ने के लिए पिलर के बीच 24 मीटर दूरी रखी गई है जो 20 मीटर टर्निंग रेडियस वाले ट्रेलर के लिए ठीक है।

एत्मादपुर विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने कहा कि समोगर और प्रकाश नगर पुल की जरूरत के लिए सीईसी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। शासन से भी पैरवी कराई जाएगी। जहां पेड़ आड़े आ रहे हैं, वहां पुल का अलाइनमेंट बदला जा सकता है, लेकिन पुल बनना चाहिए।

सेतु निगम के प्रबंधक आरबी दिवाकर का कहना है किआईआईटी रूड़की ने आरओबी के लिए तकनीकी अध्ययन किया है। उनकी रिपोर्ट में स्पष्ट है कि आरओबी जरूरी है। सीईसी के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और पक्ष रखेंगे।

सीएनजी गाड़ी है तो हाइड्रोटेस्ट से लेकर रीफ्यूलिंग तक ध्यान देना जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। बाहरी दिल्ली के टिकरी कलां में एक सीएनजी स्टेशन पर हुई दुर्घटनात्मक विस्फोट में बुधवार को तीन युवकों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद परिवार बिखर गया। आजीविका का संकट आश्रितों पर सामने चुनौती बन गई है।

ऐसे में सवाल उठता है कि सीएनजी गाड़ी यदि सफर को सस्ता करती है तो वह हाइड्रोटेस्ट से लेकर रीफ्यूलिंग तक मेंटेनेंस और सेफ्टी से जुड़ी टेक्निकल चीजों पर ध्यान मांगती है। यदि आपके पास भी सीएनजी गाड़ी है तो सुरक्षा के उपाय जानना बहुत जरूरी है।

हादसे के संबंध में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है, %प्रारंभिक जांच से पता चला है कि विस्फोट में शामिल ट्रक केवल छह सीएनजी सिलेंडर ले जाने के लिए अधिकृत था। हालांकि, घटना के समय उसमें अतिरिक्त सिलेंडर लगे हो सकते हैं। अतिरिक्त सिलेंडरों की वैधता और विस्फोट का सटीक कारण संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है। आईजीएल ऐसे मामलों में लागू सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। आईजीएल ने बताया कि यह पंप आध्या एनर्जीज के स्वामित्व और संचालन में है। इस बीच पुलिस ने लापरवाही की धारा के तहत मामला दर्ज किया है और ट्रक का मैकेनिकल निरीक्षण भी किया गया है।

बता दें कि इस हादसे में तीन कर्मचारियों की मौत, तीन घायल इस दर्दनाक हादसे में सीएनजी पंप पर कार्यरत तीन कर्मचारियों मनीष (25), ब्रह्मजीत (34) और सन्नी (30) की जान चली गई। वहीं, सुरजीत, संजय और विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल-डीजल और मालवाहक वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर बैन, अगले साल से नियम लागू

नई दिल्ली, एजेंसी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथोड़े ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और व्यावसायिक वाहनों को पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्ष 2025 में दिल्ली में बिके कुल नए हल्के मालवाहकों (एन वन श्रेणी) में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी लगभग सात प्रतिशत तक पहुंच गई है।

आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली में 14,712 नए हल्के मालवाहक वाहन बिके, जिनमें से 13,646 सीएनजी और 1,026 इलेक्ट्रिक वाहन थे, जबकि डीजल के 35 और पेट्रोल के महज चार वाहन बिके। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में एन वन श्रेणी के वाहनों की संख्या 1.06 लाख हो गई है, जिसमें 1.03 लाख सीएनजी और 1,980 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान पिथोड़े ने बताया कि यह ट्रेंड व्यावसायिक परिवहन में साफ-सुथरी तकनीक को अपनाने का स्पष्ट संकेत देता है। इसी बदलाव को रफ्तार देने के लिए आयोग ने एलान किया है कि एक जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक एन वन मालवाहक वाहनों का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद एक जुलाई 2027 से यह प्रतिबंध गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी लागू हो जाएगा। वहीं, शेष एनसीआर जिलों में एक जनवरी 2028 से नए पेट्रोल व डीजल मालवाहकों के पंजीकरण पर रोक रहेगी, हालांकि वहां सीएनजी और ईवी दोनों की अनुमति होगी। उन्होंने यह भी बताया कि हल्के वाहनों के विपरीत, 3,500 से 7,500 किग्रा वजन वाले भारी मालवाहकों (एन 2 श्रेणी) में विद्युतीकरण की रफ्तार अभी बेहद धीमी है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 के दौरान दिल्ली और पूरे एनसीआर में एक भी नया एन 2 इलेक्ट्रिक मालवाहक नहीं बिका और इस वर्ग में सीएनजी तथा डीजल का ही दबदबा रहा। पिथोड़े के अनुसार, सीएक्यूएम का यह निर्णय केवल सीधे धुएं को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि हवा में धुंध का बड़ा कारण बनने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और सेकेंडरी पर्टिकुलेट प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के तहत एनसीआर के स्टोन क्रशरों पर रिमोट कैमरे, लो-कास्ट सेंसर और क्लाउड सिस्टम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और वहां वाहनों के पहिए धोने की सुविधा अनिवार्य होगी। साथ ही, दिल्ली में चिन्हित किए गए 11 अन्य ट्रैफिक जाम वाले स्थानों को इस साल अक्टूबर तक पूरी तरह से सुचारू करने पर भी तेजी से काम चल रहा है।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट में अब 29 सितंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक की डिग्री की जानकारी देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 29 सितंबर को सुनवाई करेगा। बृहस्पतिवार को मामले पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने मामले को अन्य तारीख पर सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 29 सितंबर के लिए तय कर दिया। अपीलकर्ता ने प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को रद करने के एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी है। अपीलकर्ता के वकील ने गुरुवार को कहा कि पिछली बार कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपील दायर करने में हुई देरी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूनिवर्सिटी का मामला मेरिट के आधार पर मजबूत है और हो सकता है कि वे देरी से अपील दायर करने के मुद्दे पर आपत्ति न करें। 25 अगस्त 2025 को एकल पीठ ने सीआईसी के आदेश को रद करते हुए कहा था कि एक सार्वजनिक पद पर होने का मतलब यह नहीं है कि पीएम की सभी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए।

13 में से सिर्फ 6 जिलों के लिए ही मिल सकी जमीन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के सभी जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की योजना की गति धीमी है। यहां तक कि द्वारका सेक्टर 10 में बनने वाले मिनी सचिवालय के लिए गत जनवरी में सरकार की वित्त एवं व्यय समिति ने 212 करोड़ की मंजूरी दे दी थी, उसके बाद भी योजना आगे नहीं बढ़ सकी है। इसके लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से जमीन भी राजस्व विभाग को हस्तांतरित नहीं हो सकी है। जबकि सात जिलों में अभी जमीन की खोज भी पूरी नहीं हो सकी है। जबकि इस परियोजना को घोषित किए हुए करीब एक साल बीत चुका है। अभी तक पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी, और दक्षिण पूर्वी जिलों में ही निर्माण स्थल की पहचान हो सकी है। दिल्ली सरकार की सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। अपग्रेड करने की योजना है, जबकि उत्तरी जिले में मौजूदा डीएम कार्यालय के उन्नयन की तैयारी है। उत्तरी पश्चिमी जिले के लिए कंझावला और दक्षिणी पश्चिमी जिले के लिए द्वारका सेक्टर-10 में व्यवस्था प्रस्तावित है। दक्षिणी जिले में साकेत तथा दक्षिणी पूर्वी जिले के लिए नए परिसर की योजना है। 13 जिलों के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रविधान किया गया था।

नकली और कैंसर की दवाओं के बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश, दिल्ली-मुंबई समेत कई राज्यों से 17 अरेस्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की नकली और अस्पतालों से चोरी की गई महंगी दवाओं के एक बड़े अंतरराज्यीय अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने इस मामले में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद और हरियाणा समेत कई जगहों से अब तक 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 588 भरी हुई शीशियां, छह खाली शीशियां, सात खाली डिब्बे और 3,021 अन्य दवाएं (कुल कीमत लगभग नौ करोड़) बरामद की गई और 50 लाख रुपये नकद भी बरामद हुए हैं।

इसके अलावा पैकेजिंग मटीरियल (थर्माकोल बाक्स, बबल रोल, टेप), केमिकल (एसिटोन), हिसाब-किताब के रजिस्टर और इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए गए हैं। विशेष आयुक्त एचजीएस धालीवाल के मुताबिक, 22 जून को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कमल कुमार की टीम को इस सिंडिकेट के बारे में सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में सात टीमों का गठन किया गया। 11 जुलाई को ड्रग्स विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली और नवी मुंबई में एक साथ कई ठिकानों पर छापामारी की गई, जहां से दर्ज़लेक्स, इंफिनजी, कीट्रूडा जैसी कई महंगी कैंसर की दवाएं जब्त की गई।

यह सिंडिकेट मुख्य रूप से तीन तरीके अनाधिकृत स्रोतों से नकली दवाएं खरीदकर, नामी अस्पतालों के कर्मचारियों व नर्सिंग स्टाफ के जरिए कैंसर मरीजों की दवाएं चुराकर व सरकारी संस्थानों व स्टोर से सरकारी सप्लाई की दवाओं की हेराफेरी करके दवाएं हासिल करता था।

ये लोग एसिटोन जैसे केमिकल से दवाओं के असली बैच नंबर और एमआरपी हटा देते थे और पुरानी शीशियों या डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल कर उन्हें बिना किसी वैध लाइसेंस या बिल के बाजार में सप्लाई करते थे। सतीश कुमार, गोविंदपुरी का रहने वाला है इसे मेडिकल स्टोर पर काम करने का अनुभव है। यह बिचौलिए का काम करता था। मुकेश, गुरुग्राम का रहने वाला है।

23 लाख रुपये नकद मिले

इस मामले में जिन 17 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अभिषेक वैश्य, लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। वह 2022 से गैर-कानूनी नेटवर्क में शामिल था। इसके पास से चार लाख नकद और दवाएं बरामद की गई है। शुभम कुमार चौधरी भी लक्ष्मी नगर कार रहने वाला है। यह बिना बिल के नकद लेन-देन में शामिल था। इसके पास से 23 लाख नकद मिला है। सूरज चौधरी, लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। यह अपने भाई शुभम के साथ मिलकर 2024 से दवाओं की सप्लाई में शामिल था। गगन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद का रहने वाला है। यह होलसेल दवा व्यापारी है, जो सतीश से इंजेक्शन लेकर अभिषेक को देता था।

जांच के बाद जेल भेजे गए इमरान खान

छह डॉक्टरों की टीम ने किया चेकअप; नौ महीने बाद पत्नी और बहन से हुई मुलाकात

इस्लामाबाद, एजेंसी। पीटीआई संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मेडिकल जांच के बाद वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें हिरासत में रखना सुरक्षित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल में जांच और इलाज का आदेश दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे रजिस्ट्रार कार्यालय ने आपत्तियों के साथ वापस कर दिया। इस बीच इमरान खान को बनी गाला भेजने और विदेश में इलाज कराने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पीटीआई का कहना है कि जेल की परिस्थितियां उनकी सेहत पर असर डाल रही हैं, जबकि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उम्मीद की नई किरण बताया है।

जानकारी के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री की छह विशेषज्ञ डॉक्टरों वाली टीम ने मेडिकल जांच की। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि इमरान खान को अस्पताल में भर्ती रखने की तत्काल जरूरत नहीं है और उन्हें जेल में सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद जेल अधिकारियों ने उन्हें वापस अदियाला जेल पहुंचाया, जहां उन्हें उनकी सेल में भेज दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इमरान खान के अस्पताल पहुंचने से पहले इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरों ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, इमरान खान की मेडिकल जांच और जरूरत पड़ने पर उन्हें भर्ती करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। जिसके बाद खान को इलाज के लिए भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करने के बाद उन्हें दो दिनों के भीतर किसी चिकित्सा संस्थान में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की। हालांकि, गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने कुछ आपत्तियां उठाते हुए सरकार की पुनर्विचार याचिका वापस कर दी। इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से उनके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं। वह अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इमरान खान और उनकी पार्टी इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही है। पीटीआई का आरोप है कि इमरान खान को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर, सरकार और अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताते रहे हैं। इमरान खान ने मंगलवार को अदियाला जेल में अपनी पत्नी बुशरा बीबी और बहन नोरीन नियाजी से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल यह पहली बार था जब उनकी परिवार के इन सदस्यों से मुलाकात हुई। इससे पहले करीब नौ महीने तक दोनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जेल सूत्रों के हवाले से बताया कि क्कञ्जढ्ढ प्रमुख ने अपनी बहन के साथ करीब 15 मिनट बातचीत की। वहीं, बुशरा बीबी के साथ उनकी मुलाकात लगभग 30 से 35 मिनट चली।

बॉस, याद है जब मैं आपके साथ था: ट्रंप-कोहेन की दुश्मनी खत्म, रेडियो शो में फिर दिखी 15 साल पुरानी दोस्ती

वाशिंगट, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को अपने पुराने सहयोगी और बाद में कट्टर आलोचक बने माइकल कोहेन के रेडियो शो में शामिल हुए। यह मुलाकात इसलिए बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि कभी कोहेन ने ट्रंप को चीटो-डस्टेड कार्टून विलेन तक कहा था और अदालत तथा कांग्रेस के सामने उनके खिलाफ गवाही दी थी। लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते फिर से सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। कोहेन ने ट्रंप के गंदे कामों को छिपाने में अपनी भूमिका के लिए जेल की सजा काटी थी। ऐसे में कुछ साल पहले तक इस तरह की सार्वजनिक सुलह की कल्पना करना भी मुश्किल था।

रेडियो शो में दिखी पुरानी दोस्ती की झलक

कोहेन के 77 ङ्खक्चष्ट रेडियो कार्यक्रम पर यह इंटरव्यू गुरुवार शाम प्रसारित हुआ, जबकि इसका पूरा प्रसारण रविवार को होना है। बातचीत का माहौल बेहद दोस्ताना रहा और दोनों ने अपने उतार-चढ़ाव भरे अतीत का केवल हल्के अंदाज में जिक्र किया। ट्रंप ने कोहेन से कहा, उन्होंने तुम्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जैसा शायद ही किसी और के

साथ हुआ हो। उन्होंने आगे कहा,मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि तुमने अपनी कही हर बात वापस ले ली। तुमने बहुत बड़ी बात की है। रेडियो इंटरव्यू से कुछ समय पहले सीएनएन से बातचीत में कोहेन ने बताया कि उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से माफी के लिए फिर से आवेदन किया है। पिछली सरकार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। कोहेन ने कहा कि शुक्रवार को इस मुद्दे पर फिर बातचीत होने की उम्मीद है। ट्रंप के साथ सुलह ने कोहेन को उन पूर्व सहयोगियों की लंबी सूची में ला खड़ा किया है, जिनके राष्ट्रपति से कभी तीखे मतभेद हुए, लेकिन बाद में रिश्ते फिर सुधर गए। एलन मस्क और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस इसके हालिया उदाहरण हैं।

कोहेन और ट्रंप का रिश्ता हालांकि इन सभी मामलों से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत रहा है। कभी कोहेन कहा करते थे कि वह राष्ट्रपति के लिए गोली खा सकते हैं। ट्रंप के राजनीतिक सफर के दौरान वह उनके बेहद भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल थे। बाद में दोनों के बीच ऐसा टकराव हुआ कि 2024 के आपराधिक हश-मनी मामले में कोहेन की गवाही ट्रंप को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण साबित हुई। उस समय ट्रंप अपनी राजनीतिक वापसी की कोशिश कर रहे थे। कोहेन ने गुरुवार को कहा कि पिछले एक साल में उनकी और राष्ट्रपति की कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने अपने फैसले को समझाते हुए कहा,माफ करने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ भूल जाना। इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो हुआ, वह हुआ ही नहीं। इसका अर्थ है यह तय करने की हिम्मत रखना कि बीता हुआ कल आने वाले कल को तय नहीं करेगा।

सीरिया में तुर्किये की सैन्य विस्तार योजना पर इस्राइल की चेतावनी, राजदूत बोले- हद पार कर दी गई है

यरुशलम, एजेंसी। अमेरिका में इस्राइल के राजदूत येचिएल लेइटर ने कहा है कि इस्राइल को स्पष्ट खुफिया जानकारी मिली थी कि तुर्किये सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी का बड़े स्तर पर विस्तार करने की योजना बना रहा है। उन्होंने इसे हद पार करना बताया। द यरूशलम पोस्ट के साथ बातचीत में लेइटर ने कहा, हम तुर्किये या सीरिया में से किसी के साथ तनाव बढ़ाना या युद्ध नहीं चाहते। लेकिन एक हद पार की गई है।

उनकी यह टिप्पणी इस्राइल द्वारा सीरिया में किए गए हवाई हमलों के बाद आई है। इन हमलों की सीरिया और तुर्किये दोनों की सरकारों ने आलोचना की थी। लेइटर ने कहा, यह तुर्किये की ओर से समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा था। जिन लोगों को खुफिया जानकारी दी जानी जरूरी थी, उन्हें वह जानकारी मिल गई। जिन्हें पता होना चाहिए था कि क्या होने वाला है, उन्हें इसकी जानकारी थी। हमने स्पष्ट कर दिया था कि यह हमारे समझौतों का उल्लंघन है और इसी वजह से इस्राइल ने कार्रवाई की। लेइटर के मुताबिक, मंगलवार को अलेप्पो के पास सीरिया में अबू अल-दुहूर एयरबेस पर इस्राइल ने जो हमला किया, वह कथित तुर्किये के कदम को लेकर दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिए जाने के बाद किया गया। सीरियाई अधिकारियों ने कहा था कि एयरफील्ड पर कम से कम आठ हमले हुए। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई।

इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा था, इस्राइल ने संदेश स्पष्ट कर दिया है- ऐसा मत करो। लेइटर ने कहा कि तुर्की का कथित कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के दौरान इस्राइल और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के प्रशासन के बीच बनी समझ के खिलाफ था। इस समझ के तहत सीरिया में मौजूदा स्थिति को स्थिर रखा गया था।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में पेरिस में हुई एक बैठक के दौरान भी इन समझों की पुष्टि की गई थी। बैठक में सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी, अमेरिका के सीरिया मामलों के दूत टॉम बैरक, लेइटर, तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख गिल रीच और नेतन्याहू के सैन्य सचिव रोमन गोफमैन शामिल हुए थे। गोफमैन अब मोसाद के निदेशक हैं।

लेइटर ने कहा, इस रोक का मतलब है कि जिस तरह तुर्क आगे नहीं बढ़ते, उसी तरह हम भी आगे नहीं बढ़ते और वे हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करते। उन्होंने

कहा कि इस्राइल सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र के तहत केवल 78 वर्ग मील क्षेत्र में मौजूद है, जबकि तुर्की ने पिछले कई वर्षों में उत्तरी सीरिया में 3,500 वर्ग मील क्षेत्र पर धीरे-धीरे कब्जा बढ़ाया है। यह सीरिया के करीब पांच प्रतिशत क्षेत्र के बराबर है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों नहीं की हमले की निंदा

लेइटर ने कहा कि अमेरिका के सीरिया मामलों के दूत और तुर्किये में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक को छोड़कर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया में इस्राइली हमले की निंदा नहीं की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन की नीति पहले तय की गई स्थिति को बनाए रखने की है और इसी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले की निंदा नहीं की।

तनाव के बावजूद लेइटर ने कहा कि इस्राइल का मानना है कि सीरिया टकराव नहीं चाहता। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए स्पष्ट है कि सीरियाई हमारे साथ टकराव नहीं चाहते। लेइटर ने कहा, इसीलिए हम तुर्कों से कह रहे हैं कि वे संघर्ष पैदा न करें। इस बात के एक से अधिक संकेत हैं कि तुर्किये की नियोजित कार्रवाई सीरियाई लोगों पर थोपी गई थी। उन्होंने हमले के बाद तुर्किये और सीरिया के बयानों में अंतर की ओर भी इशारा किया। लेइटर ने कहा कि सीरिया के विदेश मंत्री शैबानी ने हमले से कुछ दिन पहले तुर्किये के एक प्रतिनिधिमंडल के सीरिया आने की बात स्वीकार की थी, जबकि तुर्किये ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा, उन्हें आपस में इसे सुलझाना चाहिए। इस्राइली राजदूत ने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर इस्राइल सीरिया के साथ सीधे बातचीत फिर शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, बातचीत फिर शुरू की जा सकती है। हम सीरियाई लोगों के साथ पहले हुई आमने-सामने की बातचीत जारी रखना चाहते हैं। तुर्किये के साथ संबंधों को लेकर लेइटर ने कहा कि इस्राइल अंकारा के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने इस्राइल के खिलाफ तुर्किये नेताओं के बयानों की आलोचना की। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से लगता है कि वे इस्राइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना पसंद करेंगे। लेइटर तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की इस्राइल के खिलाफ बार-बार की गई टिप्पणियों और तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान के उस बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्राइल मानवता पर एक दाग है।

संपादकीय | मुकदमों के घेरे में 300 से ज्यादा सांसद

देश की राजनीति में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग समय में बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। किसी भी समाज में यह उम्मीद की जाती है कि उनके जनप्रतिनिधि में उच्च स्तर की ईमानदारी, बेदाग छवि और दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। एक आदर्श राजनेता उसे कहा जाता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के कल्याण को प्राथमिकता दे। मगर जब कोई नेता गंभीर आरोपों में घिरा हो, तो वह जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर कितना खरा उतर पाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में बताया गया कि देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ चार हजार से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें तीन सौ से ज्यादा सांसद तथा चौदह मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि राजनीति में शुचिता के मानदंडों पर क्या सही मायने में अमल हो पा रहा है? साथ ही इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि राजनेताओं के लिए विशेष व्यवस्था के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे के निपटारे में इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है। देश की राजनीति में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग-अलग समय में बहस और चर्चाएं भी होती रही हैं। इसके बावजूद विधायिका में ऐसे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति बनी हुई है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सवाल सिर्फ मुकदमे जल्दी निपटाने का नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की मौजूदगी और जवाबदेही से भी

है। इसमें दो राय नहीं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होना और उसका अपराध साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं। मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसे अदालत से दोषी न करार दिया जाए। मगर सवाल यह भी है कि जो समाज अपने नेता को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखता है, अगर वह गंभीर आरोपों में घिरा हो, तो उसे किस तरह देखा जाएगा? क्या इससे ईमानदार राजनीति की शुचिता प्रभावित नहीं होगी? नैतिकता का तकाजा तो यही है कि जब किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगें, तो वह विधायी पद से खुद को अलग कर ले, लेकिन आज के समय में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपने उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने की व्यवस्था लागू की है, ताकि मतदाताओं को यह निर्णय करने में आसानी हो कि उन्हें किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। मगर, इस सब के बावजूद राजनीति में आपराधिक छवि के नेताओं के प्रवेश पर अंकुश नहीं लग पाया है। हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 2025 में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 1,243 आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया, जबकि उसी वर्ष 1,050 नए मामले भी दर्ज किए गए। हालांकि, सरकार की ओर से सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं, लेकिन शीर्ष अदालत को दी गई जानकारी में बताया गया कि वर्ष 2018 से ऐसे लंबित मामलों की संख्या लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है। जाहिर है कि सिर्फ विशेष अदालतें बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि उनके पास ऐसे मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए पर्याप्त संसाधन होना भी जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बेहद अहम- लाठी जवाब नहीं, पुलिस ज्यादती की जांच

जंतर मंतर पर जेन जी के आंदोलन के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने भी हलफनामा दिए हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बाद पूरे देश में एक बदलाव देखा जा रहा है। नई पीढ़ी अपने अधिकारों, खासकर एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी के लिए सड़कों पर उतर रही है। जेन जेड के साथ इसमें जेन अल्फा भी है। ये विरोध-प्रदर्शन व्यवस्था की खामियों को तो उजागर करते हैं, लेकिन यह भी दर्शाते हैं कि नई पीढ़ी जागरूक है और उसे पता है कि सरकार से सवाल पूछना उसका हक है। ऐसे में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बेहद अहम हो जाते हैं।

इससे जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग की जांच के लिए एक हाईपावर कमिटी गठित करने का निर्देश दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया है। वहीं, बिहार सरकार ने माना है कि एक घटना में एके-47 का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में जो पॉइंट्स बताए हैं, उसमें यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रदर्शन में आपराधिक रेकॉर्ड वाले भी घुस आए थे। इसके बावजूद ज्यादतियों के आरोपों की जांच जरूरी है, क्योंकि यह आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) नागरिकों को बोलने और अपनी बात रखने की आजादी देता है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कई फैसलों में साफ किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा हैं। जनता में सरकार की नीतियों, उसके कामकाज या किसी और वजह से असंतोष है, तो वह अपनी बात विरोध-प्रदर्शनों के माध्यम से रख सकती है। हालांकि ये अधिकार असीमित नहीं और सार्वजनिक व्यवस्था व सुरक्षा के मद्देनजर इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसका भी स्पष्ट कारण और तरीका होना चाहिए। यदि कानून-व्यवस्था का कोई मसला है, तो समाधान भी कानून के दायरे में ही होना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी किसी आंदोलन-प्रदर्शन में अड़चन डालना नहीं, उसे व्यवस्थित बनाना है।महत्वपूर्ण है कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के आरोपों की भी जांच करेगी। यह मामला महिला सम्मान और गरिमा से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान आए कुछ विडियो विचलित करने वाले हैं, और उनकी तह तक जाना जरूरी है। कुल मिलाकर, इस जांच को सिर्फ इस मामले में पुलिस की भूमिका तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसका असर आगे भी पड़ेगा। नई पीढ़ी के सवालों का जवाब संवाद है, लाठी नहीं।

आज का कार्टून

जनगणना में सिर्फ आबादी नहीं, बदलती जलवायु का हिसाब भी जरूरी

देश एक बार फिर जनगणना की तैयारी में है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली यह जनगणना स्वाभाविक रूप से अनेक प्रश्नों के केंद्र में है। क्या इसमें जातिगत गणना होगी? इससे कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यों को संसाधनों का बंटवारा किस आधार पर होगा?

कुशाग्र राजेंद्र

ये सभी सवाल महत्त्वपूर्ण हैं और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा भी, लेकिन इनके बीच एक बुनियादी सवाल लगभग अनुपस्थित है और यह कि क्या इक्कीसवीं सदी की जनगणना उन वास्तविकताओं को दर्ज करने के लिए तैयार है, जिनका सामना आज का भारत कर रहा है?

जनगणना प्रायः केवल आबादी गिनने की प्रक्रिया मानी जाती है। जबकि यह किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक दृष्टि का दर्पण होती है। कोई भी सरकार जिन बातों को जानना आवश्यक समझती है, वही उसके प्रश्नों में दिखाई देती हैं। इसलिए जनगणना केवल यह नहीं बताती कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अपने समाज को किस नजर से देख रहा है और भविष्य की चुनौतियों को किस प्रकार समझना चाहता है।

स्वतंत्र भारत की जनगणना समय के साथ बदलती रही है। आवास, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन, बैंकिंग सुविधा, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी जानकारियां इनमें क्रमशः जुड़ती गईं। इनसे शासन को विकास योजनाएं बनाने, सामाजिक असमानताओं को समझने और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लक्षित करने में बड़ी सहायता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक भारत के निर्माण में जनगणना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। उत्तर भारत में तीव्र हो रही लू, भीषण गर्मी, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएं, असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़, बुंदेलखंड और दक्षिण में गहराता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमनद झीलों के फटने का खतरा तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएं अब अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याएं नहीं रहीं। इनका सीधा असर खेती, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

विडंबना यह है कि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे पास अलग-अलग विभागों में बहुत-सी सूचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वे एक-दूसरे से जुड़ती नहीं हैं। मौसम का आंकड़ा एक संस्था के पास है, भूजल का दूसरे के पास, कृषि का तीसरे के पास और जनसंख्या का चौथे के पास। परिणाम यह है कि हमें यह तो पता है कि किसी गांव में कितने परिवार रहते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित रूप से नहीं पता कि सूखते तालाब, घटता भूजल, बदलती फसलें या बार-बार आने वाली आपदाएं वहां के लोगों के जीवन और आजीविका को किस प्रकार बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में समस्या केवल आंकड़ों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे पास जीवन और पर्यावरण को एक साथ देखने वाली सूचना व्यवस्था नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में ऐसी समग्र दृष्टि के उदाहरण पहले से मौजूद हैं। इसका एक उदाहरण

1887 में तत्कालीन मारवाड़ राज्य में जनगणना के लिए तैयार की गई ग्राम प्रश्नावली है। यह केवल गांव की आबादी या राजस्व का ब्योरा भर नहीं मांगती थी। इसमें कुओं और तालाबों की संख्या, पानी की गुणवत्ता, मिट्टी का प्रकार, चरागाह, वृक्षों की प्रजातियां, पशुधन, स्थानीय फसलें, कुटीर उद्योग, महामारी, अकाल, पलायन, स्थानीय धरोहर और गांव की सामाजिक संस्थाओं तक का विवरण दर्ज करने के 56 प्रश्न थे। गांव को केवल घरों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य, प्रकृति और स्थानीय संस्थाओं से मिलकर बने एक जीवंत तंत्र के रूप में देखा गया था।

उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में तैयार अनेक जिला गजेटियर और ग्राम अभिलेखों में वर्षा, नदियां, जंगल, मिट्टी, सिंचाई, पशुधन, स्थानीय उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधनों यहां तक कि रीति-रिवाज, खान-पान तक का विवरण जनसंख्या संबंधी सूचनाओं के साथ मिलता है। निस्संदेह इन दस्तावेजों का उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन, राजस्व निर्धारण और अकाल प्रबंधन था, पर्यावरण संरक्षण नहीं। फिर भी उन्होंने गांवों का ऐसा सामाजिक-पर्यावरणीय चित्र सुरक्षित कर दिया, जो आज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मूल्यवान स्रोत बन गया है। आधुनिक जनगणना का अपना स्पष्ट उद्देश्य होता है और उसे जनसंख्या संबंधी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मगर यह भी उतना ही सत्य है कि जलवायु परिवर्तन ने शासन की आवश्यकताओं को बदल दिया है। अगर विकास की चुनौतियां बदल रही हैं, तो सूचना तंत्र को भी समय के साथ विकसित और अद्यतन होना होगा।

दुनिया के कई देशों में अब यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि आधिकारिक सांख्यिकी और जनगणना को सतत विकास लक्ष्यों तथा जलवायु अनुकूलन की आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे अधिक उपयोगी बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग भी इस दिशा में विचार-विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे समय में भारत के पास विशेष अवसर है। हमारे पास समृद्ध ऐतिहासिक अभिलेख हैं, व्यापक डिजिटल अवसंरचना है और स्थानीय प्रशासन का विशाल तंत्र भी। आवश्यकता केवल इन सबको एक व्यापक दृष्टि से जोड़ने की है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि जनगणना का ढांचा पूरी तरह बदल दिया जाए, बल्कि इसके साथ ऐसे पूरक ग्राम या क्षेत्र आधारित प्रश्नावली जोड़े जा सकते हैं, जिनमें कुछ सीमित, मगर अत्यंत महत्त्वपूर्ण जानकारियां संकलित हों। उदाहरण के लिए, पारंपरिक जल स्रोतों की स्थिति, स्थानीय स्तर पर बार-बार आने वाली जलवायु संबंधी आपदाएं, खेती के स्वरूप में परिवर्तन, साझा प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, खास परंपरागत तरीके, जलवायु संकट के कारण पलायन और स्थानीय अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ये केवल पर्यावरण संबंधी आंकड़े नहीं होंगे, बल्कि किसी गांव और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक संदर्भ को समझने का जरिया बन सकते हैं। भारत आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन और डेटा-आधारित नीति निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम और अधिक आंकड़े जुटा सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम वही जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जिसकी आने वाले दशकों में सबसे अधिक आवश्यकता होगी।

एक सदी पहले गांवों को समझने के लिए केवल लोगों की संख्या जानना पर्याप्त नहीं माना जाता था। उनके जल स्रोत, खेत, जंगल और पशुधन भी उतने ही महत्त्वपूर्ण समझे जाते थे। आज जलवायु परिवर्तन ने हमें फिर उसी बिंदु पर खड़ा कर दिया है। इसलिए आगामी जनगणना को केवल लोगों की गिनती तक सीमित न मानकर, बदलते समाज और बदलती प्रकृति के बीच संबंधों को समझने की व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखने का समय आ गया है। संभव है कि भविष्य का सबसे प्रभावी प्रशासन वही हो, जो केवल आबादी नहीं गिने, बल्कि उन परिस्थितियों को भी समझे जिनमें वह आबादी अपना जीवन जी रही है।

दिल और दिमाग की जंग के बीच 'विचार-विनिमय'

विचार और अनुभूति मानव मन की दो अलग-अलग, लेकिन एक-दूसरे से संबंधित अवस्थाएं होती हैं। विचार जहां बुद्धि की सोच को कहा जाता है, वहीं अनुभूति दिल के अहसास या अनुभवों से जुड़ी होती है। यों आमतौर पर कहा जाता है कि कुछ लोग दिल से सोचते हैं, तो कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं। जो दिमाग से सोचते हैं, वे हर बात में अपना लाभ-हानि देखते हैं और जो लोग दिल से सोचते हैं, वे दूसरों के दुख-दर्द से भी दुखी हो जाते हैं या दूसरों की खुशी में खुश भी हो जाते हैं।

राजेंद्र वामन काटदरे

कई बार देखा जाता है कि हम अपने किसी मित्र या परिजन को चिंताग्रस्त या चुपचाप बैठे देखते हैं, तो पूछ लेते हैं कि क्या विचार कर रहे होज्या क्या सोच रहे हो। हम किसी समस्या में उलझे अपने मित्र को या किसी अपने को सलाह भी दे देते हैं कि अब ज्यादा मत सोचो, ज्यादा विचार मत करो, सब ठीक ही होगा। मगर अब 'ज्यादा मत सोचो' कहने भर से दिमाग में चल रहे विचार-चक्र को या दिल में उठ रहे भावनाओं के बवंडर को रोकना भला हमारे या किसी के भी हाथ में कहां होता है?

यह विडंबना ही है कि मनुष्य का विचार-चक्र सतत चलता ही रहता है। सुख हो या दुख, मनुष्य अकेला हो या किसी महफिल में, उसके दिमाग में विचार आते ही रहते हैं। वह हरदम, हर पल कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। यहां तक कि सोते हुए भी मानव के दिमाग का एक हिस्सा जागृत रहता ही है, जो दिनभर में सोची गई, देखी गई बातें दृश्य रूप में या स्वप्न के रूप में दिखाता रहता है। विचार का अर्थ सोच, खयाल या दिमाग में उठने वाली कल्पना या राय से लगाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सोच-विचार एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। यों विचार या चिंतन को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसमें

मानव मन किसी बात या समस्या के अच्छे या बुरे दोनों पहलुओं पर सोचता रहता है और अपने मन-मस्तिष्क में मंथन-चिंतन करता रहता है। जब मनुष्य सोच-विचार करता है, तो इसमें तर्क, योजना, शब्द-चित्र हो सकते हैं। यानी सोच-विचार को किसी चीज या समस्या को समझने का मानसिक तरीका भी माना जा सकता है। घर के बुजुर्ग प्रायः कहते-समझाते हैं कि हमेशा अच्छा सोचना-विचारना चाहिए, क्योंकि अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। दरअसल, हमारी सोच और विचारों का हमारे आचरण पर प्रभाव भी साफ-साफ दिखता है। जो लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, वे आमतौर पर दूसरों की मदद करने में भी अव्वल ही रहते हैं। जो बुरा सोचते हैं, वे औरों का या कई बार अनजाने में खुद का भी बुरा कर बैठते हैं। अगर कहा जाए कि मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और नकारात्मक विचार हमारा आत्मविश्वास खत्म कर, जीती हुई बाजी को भी हरवा सकते हैं। एक मराठी कहावत है कि 'मन चिंती, ते वैरी न चिंती' यानी कई बार हमारा मन इतनी बुरी बातें सोच लेता है, जो शायद हमारे किसी दुश्मन ने भी न सोची होंगी। घर के किसी सदस्य को किसी दिन घर आने में देर हो जाए और उससे संपर्क न हो रहा हो, तो मन में खराब विचार पहले आने लगते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। फिर हमारे विचारों की गति इतनी होती है कि पलभर में हम विचारों में ही सात समंदर पार कर सकते हैं। विचारों के बारे में एक मजेदार बात और भी है कि हम अपने विचारों का विनिमय भी कर सकते हैं। सुनने में अटपटा लगता है, क्योंकि विचार करना एक मानसिक प्रक्रिया है और विनिमय से तात्पर्य तो किसी वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा या मुद्रा का आदान-प्रदान करना है। मगर जब ये दोनों शब्द साथ में आते हैं, तो एक नया शब्द विचार-विनिमय बनता है।विचार-विनिमय शब्द बताता है कि विचारों का भी आदान-प्रदान किया जा सकता है, बल्कि किया भी जाता है। दफ्तरों में होने वाली बैठकों में, जहां दफ्तर के अफसर या सहयोगी किसी समस्या विशेष को सुलझाने के लिए अपने-अपने विचार प्रकट करते हैं और इन्हीं अच्छे विचारों का एकत्रित स्वरूप, कार्यशैली के रूप में अपनाकर उक्त समस्या के निराकरण की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार विविध संस्थाओं द्वारा किसी विषय-विशेष पर सेमिनार, विचार-विनिमय के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। जिस प्रकार दूध की मलाई या दही को मथने पर घी निकलता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी समस्या पर, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, विचार-विनिमय करने से या विचार-मंथन करने से उसका हल या उस समस्या का निदान भी मिल ही जाता है। यों विचार-विनिमय से सिर्फ समस्याओं के हल ही नहीं मिलते, बल्कि अनेक लोग अपने विचारों का विनिमय मुद्रा कमाने के लिए भी करते हैं। सच नहीं लगता ना कि किसी के विचारों के लिए कोई अन्य मुद्रा या पैसा क्यों देगा? लेखक कहानी या लेख लिखकर, कविता या गीत लिखकर, हास्य कलाकार अपनी कल्पना या अपने विचारों से कुछ चुटकुले रच कर मुद्रा या पैसा कमा सकते हैं और कमाते भी हैं। विचारपूर्वक काम करने से किसी भी काम की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। किसी ने कहा भी है कि पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसे में सकारात्मक सोचें और यदि सादा जीवन एवं उच्च विचार अपना लिया जाए, तो जीवन सफल हो सकता है।

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप

त्रिसा-गायत्री ने दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी को हराया, महिला डबल्स में मेडल पक्का

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी जी यिफान और झांग शुक्सियन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। त्रिसा-गायत्री की जीत ने देश के लिए मेडल पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने एक गेम पीछे रहने के बाद चीनी जोड़ी पर 16-21, 21-15, 21-13 से जीत दर्ज की और महिला डबल्स में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली दूसरी जोड़ी बन गई। इससे पहले महिला डबल्स में 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने कांस्य पदक जीता था। शुरुआत में भारतीय जोड़ी कमजोर दिखी क्योंकि जिया और झांग ने 6-2 की बढ़त बना ली और शुरुआती गेम तक अपनी बढ़त बनाए रखी। त्रिसा और गायत्री ने धीरे-धीरे अपनी आक्रामक रिदम पाई, अपने पावरफुल स्मैश और नेट के दम पर अंतर को 8-9 कर दिया। हालांकि, रिकवरी इतनी नहीं थी कि चीनी खिलाड़ी को 11-8 की बढ़त के साथ ब्रेक में जाने से रोका जा सके और आखिरकार शुरुआती गेम 21-16 से जीत लिया। दूसरे गेम भारतीयों ने अपने विरोधियों को वैसा नियंत्रण नहीं करने दिया, लंबी रैलियों में उनका मुकाबला किया और दबाव में डिफेंड करते हुए इंटरवल पर 11-10 की मामूली

बढ़त हासिल की। वहां से, त्रिसा और गायत्री और ज्यादा आक्रामक हो गईं। उनके क्रॉस-कोर्ट अटैक ने बार-बार चीनी जोड़ी को कोर्ट के पार खींचा, जबकि उनके डिफेंस ने जिया और झांग के दबाव को झेला। इंडियन्स ने 17-14 की बढ़त के साथ शुरुआत की और फिर गेम 21-15 से खत्म करके निर्णायक बना दिया। निर्णायक गेम में 4-4 से बराबरी की शुरुआत के बाद, त्रिसा ने एक जोरदार स्मैश से ब्रेकथ्रू पाया, और भारतीय जोड़ी ने बढ़त बना ली। लगातार सात पॉइंट्स ने मैच का पासा पलट दिया, जिससे वे 4-4 से 9-4 पर आ गए। त्रिसा के अटैक ने चीनी जोड़ी को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। भारतीय जोड़ी ने 11-5 की बड़ी बढ़त के साथ इंटरवल में एंट्री की। साइड बदलने के बाद, जिया और झांग ने थोड़ी देर के लिए अपनी चुनौती को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने लगातार तीन पॉइंट्स जीतकर अपनी लय वापस पा ली। चीनी जोड़ी पर बढ़ते दबाव के साथ, उनके गेम में गलतियां होने लगीं। 18-9 पर, भारतीय बस बराबरी पर थे। झांग के शॉट को आउट दिए जाने के बाद एक समीक्षा से नतीजे में ज्यादा बदलाव नहीं आया। चीनी जोड़ी की दो और गलतियों ने त्रिसा और गायत्री को निर्णायक पाइंट दिला दिए। इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी का पदक पक्का हो गया।

श्रीलंका ने कोलंबो टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम का किया ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने भारत के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है। 14 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर सहन अराचिगे और बल्लेबाज कामिल मिशारा को शामिल किया गया है। पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए दिनेश चांदीमल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट रहे पासिंदु सोरियाबंदारा को भी टीम से बाहर रखा गया है। दूसरे ओपनर निशान मदुश्का को जगह नहीं मिली, जबकि गेंदबाजी ऑलराउंडर रमेश मेंडिस और तेज गेंदबाज दिलशान मदुश्का भी टीम में जगह नहीं बना सके। अराचिगे को भारत ए के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। अराचिगे ने भारत ए के खिलाफ हाल ही में श्रीलंका ए क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी और बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अराचिगे ने पहले मैच में 72 और दूसरे मैच में 127 रन की पारी खेली थी। दो अनाधिकारिक मैचों की सीरीज में भारतीय साई सुदर्शन के बाद अराचिगे दूसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे थे। अराचिगे को टेस्ट डेब्यू का इंतजार है। मिशारा लंका प्रीमियर लीग 2026 में शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने हाल के सीजन में नौ पारियों में 411 रन बनाए थे। उन्होंने गॉल गैलेंट्स के खिलाफ शतक भी बनाया था। वे मेजर क्लब्स टी20 कॉम्पिटिशन में शानदार फॉर्म में थे और महज 72 गेंदों पर 145 रन की पारी खेली थी। श्रीलंका पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। सीरीज बचाने के लिए श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। पहला टेस्ट टीम इंडिया ने 165 रन से जीता था।

श्रीलंका टीमः
लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, पासिंदू सोरियाबंदारा, कामिंडू मेंडिस (उपकप्तान), धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सहन अराचिगे, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, मिलन रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो।

कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने टीम इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी की

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंडिया हाउस में भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की। भारतीय उच्चायुक्त झा ने गुरुवार रात भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही श्रीलंकाई टीम की भी मेजबानी की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी दी है और इसे एक 'यादगार शाम' बताया है। बीसीसीआई ने अपने एक्स में लिखा, 'कोलंबो में एक यादगार शाम। श्रीलंका में इंडिया के उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले कोलंबो के इंडिया हाउस में भारतीय टीम की मेजबानी की। ' झा ने दोनों टीमों की मेजबानी करके खुशी जाहिर की और कार्यक्रम की कुछ झलकियां एक्स पर साझा की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'टीम इंडिया के साथ चीयर कर रहा हूं। श्रीलंका में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचों के दौरान भारतीय और श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीमों की मेजबानी करके खुशी हो रही है। खेल के लिए एक जैसे जुनून से बंधा, क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा रहने वाले रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। ' भारत ने गाले में पहले टेस्ट में 165 रन की बड़ी जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। गाले टेस्ट में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन बनाए थे। श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटकर 178 रनों से पिछड़ी थी। भारतीय टीम दूसरी पारी में 193 रन पर सिमटी और पहली पारी में मिले 178 रन की बढ़त के आधार पर श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका दूसरी पारी में 206 रन पर सिमट गई और 165 रन से मैच हार गई। दूसरी पारी में भारत के लिए मानव सुथार ने 6 विकेट लिए थे।

सिनसिनाटी ओपन

इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंची

सिनसिनाटी, एजेंसी। एलेना रयबाकिना को सिनसिनाटी ओपन क्वार्टर फाइनल मैच से बाएं टखने में चोट के कारण बाहर होना पड़ा। इंजरी की वजह से जहां वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं, वहीं उनकी विपक्षी इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंच गईं। मैच के दौरान स्वियाटेक 4-1 से आगे थीं और रयबाकिना 40-15 पर सर्व कर रही थीं। उसी समय रयबाकिना के लिए मुश्किल शुरू हुई। रयबाकिना नेट पर एक रैली खत्म नहीं कर सकीं। डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के अनुसार, अगले पॉइंट पर उन्हें अपनी पहली सर्व पर पुश करने में मुश्किल हुई, जो सिर्फ तीन शॉट तक चली, और गेम के बीच में मेडिकल जांच के बाद, रयबाकिना ने कुछ देर बाद मैच खत्म करने का फैसला किया। रायबाकिना ने कहा, 'मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सर्व से पुश भी नहीं कर पा रही थी। चलने में दर्द हो रहा है। एमआरआई के बाद समस्या के बारे में और पता चलेगा। ' उन्होंने कहा, 'यह मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। कनाडा में बहुत सारे मैच खेलने और यहां लगातार दो मैच खेलने के बाद और मैच से पहले ठीक लग रहा था लेकिन बदकिस्मती से एक गलत मूवमेंट, एक लैंडिंग, और समस्या शुरू हो गई। ' बुधवार को चौथे राउंड में सारा बेजलेक

एलेना रयबाकिना इंजरी की वजह से बाहर

सिनसिनाटी ओपन

आर्थर फिल्स ने थियागो अगस्टिन टिरेंटे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

सिनसिनाटी, एजेंसी। आर्थर फिल्स ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फिल्स ने 64 मिनट तक चले मुकाबले में थियागो अगस्टिन टिरेंटे को 6-3, 6-2 से हराया। फिल्स ने इस सीजन के तीसरे एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 22 साल के फिल्स एक सीजन में तीन मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी बन गए। उनसे पहले गाइ फॉरगेट ने 1991 में यह उपलब्धि हासिल की थी। फरवरी में आठ महीने की चोट के बाद वापसी करते हुए फिल्स का शानदार सीजन रहा है। एटीपी जीत/हार इंडेक्स के मुताबिक, इस साल फ्रेंचमैन का टूर-लेवल रिकॉर्ड 30-10 रहा है, जिसमें बार्सिलोना में एक खिताब और मियामी और मैड्रिड में मास्टर्स 1000 इवेंट्स के सेमीफाइनल में पहुंचना शामिल है।

पहले सेट में 4-3 पर एक अहम ब्रेक हासिल करने के बाद, फिल्स ने लगातार जबरदस्त फोरहैंड लगाए, जिससे टिरांटे लगातार बैकफुट पर रहे। एटीपी के मुताबिक, 22 साल के खिलाड़ी ने दूसरे सेट में अर्जेंटीना के खिलाड़ी की सर्विस दो बार तोड़ी और पूरे मैच के दौरान उन्हें कभी भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। अब वह टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए फ्लेवियो कोबोली से भिड़ेंगे, दोनों खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचना चाहते हैं।

कोबोली ने घरेलू पसंदीदा टॉमी पॉल के खिलाफ 2-6, 6-3, 6-4 से जीत हासिल की और ओहियो में अपने पहले मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंच गए। 24 साल के खिलाड़ी अब जून में रोलैंड गैरोस चैंपियनशिप मैच में पहुंचने के बाद अपने पहले सेमीफाइनल की तैयारी करेंगे। वह 2024 और 2025 में जैनिक सिनर के बाद सिनसिनाटी में अंतिम चार में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे इटैलियन खिलाड़ी हैं। पॉल के खिलाफ जीत के साथ, कोबोली ने यह भी पक्का कर लिया कि वह सोमवार को एटीपी रैंकिंग में अपने करियर की नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वह अभी लाइव रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 6 पर हैं।

जैकब मार्टिन को 22 साल पुराने में पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत दी है। 2004 के इस मामले में कोर्ट ने मार्टिन को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर पर फर्जी यूके आव्रजन स्टाम्प, यात्रा व्यवस्था और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा आरोप लगाया गया था, जिसे साबित नहीं किया जा सका। अदालत को वित्तीय लेनदेन या अजवा स्पोर्ट्स क्लब पर उनके स्वामित्व या नियंत्रण से जुड़ा कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। कई गवाह भी इन आरोपों को साबित करने में विफल रहे। मीडिया से बात करते हुए मार्टिन ने बताया कि यह मामला 2004 में उनकी टीम के एक सदस्य द्वारा ब्रिटेन का वीजा समाप्त होने के बाद वहां रुकने और फर्जी आव्रजन स्टाम्प लगवाकर भारत लौटने के बाद शुरू हुआ था। मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था। बाद में उनका नाम मामले में जोड़ दिया गया। घटना के बारे में मार्टिन ने कहा, 2004 में टीम इंग्लैंड खेलने गई थी। जो टीम 2004 में इंग्लैंड गई थी, उसमें से एक लड़के को छोड़कर बाकी सब वापस आ गए। वीजा की वैधता छह महीने की थी, वह छह महीने तक रह सकता था। वह इससे अधिक समय तक रुका रहा। किसी के जरिए उसने वहां फर्जी स्टैंपिंग करवा ली। फर्जी स्टैंपिंग कराने के बाद जब वह भारत वापस आया, तो उसे ब्रिटेन से डिपोर्ट कर दिया गया था। उसे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और फिर उससे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा, 'मेरा नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन जब जांच हुई, तो एक बड़ा नाम होने के नाते मुझे इस मामले में घसीटा गया।

यूएस ओपन 2026: प्राइज मनी में भारी वृद्धि

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खिलाड़ियों द्वारा प्राइज मनी बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों की ये मांग पूरी होने वाली है। यूएस ओपन में इस बार खिलाड़ियों के प्राइज मनी में इजाफा होने वाला है। यूएस ओपन की प्राइज मनी में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। खिलाड़ियों की कुल सैलरी बढ़कर 108 मिलियन डॉलर हो गई है। टूर्नामेंट से पहले, यूएसटीए (यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन) ने एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की। यूएसटीए के सीईओ क्रेग टिली ने कहा कि यह कदम खेल के आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकता है। यह एथलीटों में कई सालों के निवेश में एक अहम पहला कदम है क्योंकि यूएस ओपन खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा आर्थिक मौका और खिलाड़ियों, फैंस और पार्टनर्स के लिए टेनिस में सबसे कीमती प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एकल विजेता को 52.65 करोड़ मिलेंगे। वहीं, एकल फाइनल में हारने वाले खिलाड़ी को करीब 26.80 करोड़ रुपये (2.8 मिलियन) दिए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को लगभग 7.46 करोड़ रुपये (780,000) और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले प्लेयर्स को करीब 13.88 करोड़ रुपये (1.45 मिलियन) मिलेंगे। डबल्स मुकाबलों में पुरुष, महिला और मिक्स जीतने वाले प्लेयर्स को लगभग 9.57 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिन्हें वे आपस में बांटेंगी। वहीं उपविजेता टीमों को करीब 5,00,000 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। इसके अलावा, व्हीलचेयर सिंगल्स के चैंपियन्स को लगभग 99 लाख रुपये (1,04,000) की इनामी राशि मिलेगी। पहले ही मैच में हारकर बाहर होने वाले खिलाड़ी को भी लगभग भारतीय रुपये में 1.34 करोड़ रुपये (140,000) मिलेंगे। यूएस ओपन रोमांचक होने वाला है। पिछले 4 महीने से पेशेवर टेनिस से दूर रहे पूर्व चैंपियन कार्लोस अल्काराज अपना खिताब बचाने के लिए उतरेंगे। अल्काराज ने अप्रैल के बाद से एक भी मैच नहीं खेला है। उन्हें बार्सिलोना ओपन के दौरान कलाई में चोट लग गई थी। चोट की वजह से वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और कई दूसरे टूर्नामेंट से भी बाहर रहे। यूएस ओपन 2026 की शुरुआत 23 अगस्त से होगी और 13 सितंबर को पुरुषों के फाइनल के साथ खत्म होगा।

डोपिंग को लेकर नाडा की बड़ी कार्रवाई, इस भारतीय भाला फेंक एथलीट पर लगाया 10 साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने डोपिंग को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। ओलंपियन भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर दूसरे डोपिंग अपराध के लिए 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्व एशियाई रजत पदक विजेता और ओलंपियन भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर दूसरे डोपिंग अपराध के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के अनुशासनात्मक पैनल ने 10 साल का प्रतिबंध लगाया है। शिवपाल प्रतिबंधित पदार्थ मेथाएंडिएनोन के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। 31 साल की उम्र में यह प्रतिबंध उनके खेल करियर का अंत कर सकता है। शिवपाल ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

पहले लगा था चार साल का प्रतिबंध

नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने अगस्त 2022 में उन्हें डोपिंग उल्लघंन का दोषी मानते हुए 2021 से चार साल का प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 2025 तक चलना था, लेकिन शिवपाल ने नाडा के अपील पैनल के सामने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि उनकी डोप जांच में पॉजिटिव आने के पीछे दूषित सप्लीमेंट्स जिम्मेदार थे। जनवरी 2023 में अपील पैनल ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए प्रतिबंध को चार साल से घटाकर सिर्फ एक साल कर दिया।

कट शॉट बना यशस्वी जायसवाल का 'दुश्मन', 27 गेंदों में 4 बार फंसे...कोलंबो टेस्ट से पहले की गंभीर तैयारी

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो के एसएससी मैदान में 23 अगस्त (रविवार) से होना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले यशस्वी जायसवाल अपनी एक खास कमजोरी पर जोरदार मेहनत कर रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है. मुकाबले से दो दिन पहले यशस्वी जायसवाल ने नेट्स में अपनी उस कमजोरी पर खास तौर पर काम किया, जो गॉल टेस्ट में फिर सामने आई थी. ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंदबाजों की गेंद पर कट शॉट खेलने की उनकी आदत इन दिनों परेशानी बनती दिख रही है. भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल अब तक 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उन्होंने हर टेस्ट अलग-अलग मैदान पर खेला है. टेस्ट डेब्यू से लेकर अब तक उनका सफर कैरेबियाई देशों, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और अब श्रीलंका तक पहुंच चुका है. सिर्फ तीन साल के टेस्ट करियर में ही जायसवाल भारतीय बल्लेबाजी की अहम कड़ी बन चुके हैं. सफेद गेंद क्रिकेट वाली उनकी आक्रामकता

नेट्स में शुरू हुआ सुधार का काम

जायसवाल के गलत शॉट खेलने का प्रतिशत भी बढ़ा है. पहले यह आंकड़ा 31.1 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 48.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है. यही वजह रही कि शुक्रवार को कोलंबो के स्पष्ट मैदान पर भारत के तेज गेंदबाजों ने नेट्स में उन्हें लगातार इस एरिया में परखने की कोशिश की.

कट शॉट बना परेशानी की वजह?

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के तेज गेंदबाज फर्नांडो ने जायसवाल को ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद पर फंसाया. जायसवाल गेंद को कट करने के लिए गए, लेकिन किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर डिकवाला के पास चली गई. आंकड़े बताते हैं कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलते हुए आउट होने का पैटर्न हाल के महीनों में बढ़ा है. पिछले साल अक्टूबर में भारतीय घरेलू टेस्ट सीजन शुरू होने के बाद से जायसवाल सिर्फ 27 गेंदों में तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलने के प्रयास में चार बार आउट हो चुके हैं. वहीं टेस्ट डेब्यू से लेकर पिछले साल इंग्लैंड दौरे तक, करीब दो साल के दौरान वह 190 गेंदों में सिर्फ चार बार इस शॉट पर आउट हुए थे. यानी हाल के समय में यह कमजोरी ज्यादा साफ होकर सामने आई है.

एशियाई चैंपियनशिप में जीता था रजत

शिवपाल के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतना है। दोहा में उन्होंने 86.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह पदक हासिल किया था। हालिया मामलों में कार्रवाई का सामना करने वाले शिवपाल अकेले भारतीय एथलीट नहीं हैं। धाविका एमवी जिल्ना को भी दूसरे डोपिंग उल्लघंन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया गया और वह मेफेंटरमाइन के लिए पॉजिटिव मिलीं। इससे पहले 2021 में शिवपाल का डोप नमूना प्रतियोगिता से बाहर की गई जांच में एक स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव आया था।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए न्यायाधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यालय नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेलः alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670